हिन्दी दैनिक

लखनऊ जंक्शन

RNI NO.-UPHIN/2015/64743 Email-lkojunction@gmail.com

वर्ष: 11 अंक: 163 लखनऊ, शुक्रवार 06 फ़रवरी 2026 पृष्ठ: 04 मूल्य: 01 रूपये

दिल्ली विस्फोट के बाद बड़ी कार्रवाई!

अल फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जवाद अहमद सिद्दीकी गिरफ्तार

दिल्ली ब्यूरो

नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा (Crime Branch) ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए अल फलाह विश्वविद्यालय के चेयरमैन जवाद अहमद सिद्दीकी को गिरफ्तार कर लिया है। यह गिरफ्तारी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) की शिकायतों पर दर्ज दो प्राथमिकियों (FIR) के आधार पर की गई है। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा कार्यवाही शुरू करने के बाद दिल्ली पुलिस ने यह कार्रवाई की है। लाल किले के पास हुए विस्फोट के बाद अपराध शाखा ने निजी विश्वविद्यालय के कामकाज से संबंधित कथित अनियमितताओं और धोखाधड़ी के संबंध में मामले दर्ज किए थे। अधिकारी ने बताया कि सिद्दीकी को स्थानीय अदालत में पेश किया जहां से उसे आगे की

पूछताछ के लिए चार दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया।

म्क की सक्रियता और पुलिस की कार्रवाई

इस मामले में मोड़ तब आया जब प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने भी वित्तीय अनियमितताओं को देखते हुए अपनी कार्यवाही शुरू कर दी।

ED की सक्रियता के बाद दिल्ली पुलिस ने त्वरित कदम उठाते हुए चेयरमैन सिद्दीकी को हिरासत में लिया।

विवादास्पद स्टाफ सदस्यों के लिंक

अल फलाह यूनिवर्सिटी तब जांच के दायरे में आ गई जब रिपोर्ट्स में पता चला कि 2000 के लाल किले ब्लास्ट में दोषी ठहराए गए डॉ. उमर नबी, जिसमें 13 लोगों की जान गई थी, यूनिवर्सिटी में काम कर रहे थे। जांचकर्ताओं ने दो सहयोगियों, डॉ. मुज़म्मिल शकील और डॉ. शाहीन शाहिद की भी पहचान की, जो एक तथाकथित व्हाइट–कॉलर आतंकी नेटवर्क से जुड़े थे और जिनके संस्थान से संबंध थे। इन खुलासों से राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान बढ़ा और यूनिवर्सिटी की हायरिंग प्रक्रियाओं के बारे में चिंताएं पैदा हुईं।

मान्यता और वित्तीय चिंताएं

नवंबर में, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल (NAAC) द्वारा कथित तौर पर झूठे मान्यता दावों के संबंध में कारण बताओ नोटिस जारी करने के बाद यूनिवर्सिटी की आधिकारिक वेबसाइट को ऑफलाइन कर दिया गया था। इसके बाद प्रवर्तन निदेशालय ने यूनिवर्सिटी की फंडिंग और वित्तीय लेनदेन, विशेष रूप से इसके मेडिकल स्टाफ से जुड़े लेनदेन की जांच करने की योजना की घोषणा की है। अधिकारियों ने इस बात पर ज़ोर दिया है कि जांच जारी है और जैसे–जैसे अधिकारी यूनिवर्सिटी के रिकॉर्ड की समीक्षा करेंगे और सिद्दीकी से विस्तार से पूछताछ करेंगे, वैसे–वैसे और भी घटनाक्रम होने की उम्मीद है। यह गिरफ्तारी संस्थान में प्रशासनिक और वित्तीय अनियमितताओं की जांच में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो हाल के महीनों में बढ़ती नियामक जांच के दायरे में रहा है।

चाइनीज मांझे से मृत्यु हत्या जैसी : सीएम योगी

चाइनीज मांझे से हो रही दुर्घटनाओं पर मुख्यमंत्री का कड़ा रुख

उपलब्धता कैसे हो रही है चाइनीज मांझे की ? सीएम ने दिया पुलिस को सघन छापेमारी का निर्देश
राज्यव्यापी अभियान चलाकर एक्शन लेने के निर्देश, कार्रवाई की होगी उच्चस्तरीय समीक्षा

लखनऊ ब्यूरो

लखनऊ। प्रदेश में चाइनीज मांझे से होने वाली दुर्घटनाओं को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कड़ा रुख अपनाया है। उनका मानना है कि किसी व्यक्ति की चाइनीज मांझे की वजह से होने वाली मृत्यु हत्या की तरह है। इस तरह के मामलों में संबंधित के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि चाइनीज मांझा पूरी तरह प्रतिबंधित है और इसके बावजूद इसकी उपलब्धता गंभीर चिंता का विषय है। उन्होंने पुलिस को प्रदेशव्यापी सघन छापेमारी अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान चाइनीज मांझे की बिक्री ही नहीं, बल्कि भंडारण व परिवहन पर भी कठोर नजर रखी जाएगी।

जन–सुरक्षा से कोई समझौता नहीं : योगी

सीएम योगी ने प्रदेश भर में विशेष अभियान चलाकर चाइनीज मांझे की आपूर्ति श्रृंखला को पूरी तरह तोड़ने

के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने इस अभियान की प्रगति और कार्रवाई की उच्च स्तर पर नियमित समीक्षा करने का भी निर्देश दिया है, ताकि किसी भी स्तर पर लापरवाही न हो। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि जनता की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जा सकता है। चाइनीज मांझा न केवल कानूनन अपराध है, बल्कि यह आमजन, बच्चोंऔर पशु–पक्षियों के लिए जानलेवा खतरा भी है। सरकार का लक्ष्य है कि प्रदेश को इस खतरनाक मांझे से पूरी तरह मुक्त किया जाए।

संक्षिप्त समाचार

राहुल गांधी को लेकर राज्यसभा में सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस, कांग्रेस का बहिर्गमन

एजेंसी

नयी दिल्ली। कांग्रेस ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को लोकसभा में बोलने नहीं देने का मुद्दा गुरुवार को राज्यसभा में भी उठाया जिसे लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोक झोक हुई जिसके बाद कांग्रेस ने सदन से बहिर्गमन किया। सदन में विधायी दस्तावेज रखे जाने के बाद सभापति ने नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे को बोलने का अवसर दिया। खरगे ने यह मुद्दा उठाते हुए कहा कि सरकार विपक्ष की आवाज दबा कर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को प्रभावित कर रही है वहीं नेता सदन जगत प्रकाश नड्डा और संसदीय कार्य मंत्री किरेण रिजिजू ने कहा कि लोकसभा की चर्चा को लेकर राज्यसभा में मुद्दा नहीं उठाया जा सकता।

सदन में विपक्ष का हंगामा, लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर ध्वनिमत से प्रस्ताव पारित

एजेंसी

नयी दिल्ली। लोकसभा ने बृहस्पतिवार को विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव को ध्वनिमत से पारित कर दिया। इसके तत्काल बाद ही सदन की कार्यवाही दोपहर दो बजे तक स्थगित कर दी गई। धन्यवाद प्रस्ताव पर सदन में हुई चर्चा का प्रधानमंत्री द्वारा सदन में जवाब देने की परंपरा है, लेकिन गतिरोध की स्थिति के बीच प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का जवाब लोकसभा में नहीं हुआ और प्रस्ताव को पारित कर दिया गया।

विपक्ष की लोकसभा में सत्तापक्ष के सदस्यों पर हमले की योजना थी : गिरिराज सिंह

एजेंसी

नयी दिल्ली। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने आरोप लगाया है कि विपक्षी सांसदों की बुधवार को लोकसभा में सत्ता पक्ष के सदस्यों पर हमले की योजना थी। लोकसभा में बुधवार को विपक्ष की कुछ महिला सांसदों को सत्तापक्ष की सीटों की तरफ आते हुए देखा गया। यह घटनाक्रम उस वक्त हुआ, जब कई बार के स्थगन के बाद शाम पांच बजे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देना था। विपक्षी सदस्यों के हंगामे के समय प्रधानमंत्री सदन में नहीं थे।

मेघालय में दर्दनाक हादसा, अवैध कोयला खदान में भीषण विस्फोट से कई मजदूरों की मौत, रेस्क्यू जारी

एजेंसी

शिलांग। मेघालय के ईस्ट जयंतिया हिल्स जिले के एक सुदूरवर्ती इलाके में गुरुवार को एक अवैध कोयला खदान में भीषण डायनामाइट विस्फोट होने कई मजदूरों की मौत हो गई और कई अन्य घायल घायल हो गया है। वहीं अधिकारियों ने अंदेशा जताया है कि मलबे में और भी मजदूर फंसे हो सकते हैं, जिससे मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। विस्फोट की सूचना मिलते ही बम निरोधक दस्ता, फोरेंसिक विशेषज्ञ, राज्य आपदा मोचन बल और अग्निशमन सेवा की टीमें स्थिति का जायजा लेने के लिए मयन्सांगट थांगस्को क्षेत्र में पहुंच गईं। ईस्ट जयंतिया हिल्स के पुलिस अधीक्षक विकास कुमार ने एक न्यूज एजेंसी बताया कि यह एक डायनामाइट विस्फोट था। उन्होंने बताया कि खदान

से अब तक चार शव बरामद किए जा चुके हैं, जबकि झुलसे हुए एक घायल व्यक्ति को इलाज के लिए शिलांग रेफर किया गया है। प्रारंभिक रिपोर्टों के अनुसार, एक पहाड़ी पर अवैध खनन किया जा रहा था। यह विस्फोट के कारण ढह गई, जिससे वहां काम कर रहे कई खनिक दब गए।इससे पहले 23 दिसंबर, 2025 को भी थांगस्को गांव में एक विस्फोट हुआ था, जिसमें दो खनिकों की जान चली गई थी। गौरतलब है कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने अप्रैल 2014 में मेघालय में खतरनाक रैट–होल कोयला खनन पर इसके अवैध और अवैज्ञानिक स्वरूप के कारण प्रतिबंध लगा दिया था। मेघालय हाई कोर्ट द्वारा कोयले से जुड़े मामलों की निगरानी के लिए नियुक्त किए गए न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) ब्रोजेंद्र प्रसाद काटाके ने कहा था कि सरकार के ऐसी गैर–कानूनी गतिविधियों को रोकने के आश्वासन के बावजूद, राज्य में अवैध कोयला खनन और ट्रांसपोर्टेशन जारी है। हालांकि मुख्यमंत्री कोनराड संगमा ने उस समय दावा किया था कि जिला प्रशासन सतर्क है और अवैध खनन से जुड़े 1,000 से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं।

भारत-यूएस ट्रेड डील पर आया बड़ा अपडेट, जल्द जारी हो सकता है जॉइंट स्टेटमेंट

एजेंसी

नयी दिल्ली। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बृहस्पतिवार को कहा कि भारत और अमेरिका के

द्विपक्षीय व्यापार समझौते के पहले चरण पर संयुक्त बयान को चार से पांच दिन में अंतिम रूप देने और उस पर हस्ताक्षर करने की संभावना है। संयुक्त बयान पर हस्ताक्षर होने के बाद अमेरिका, भारत पर शुल्क घटाकर 18 प्रतिशत करने का कार्यकारी आदेश जारी करेगा। भारतीय वस्तुओं पर वर्तमान में 25 प्रतिशत का जवाबी शुल्क और रूसी कच्चे तेल की खरीद को लेकर 25 प्रतिशत का अतिरिक्त शुल्क लगता है। गोयल ने पत्रकारों को बताया कि समझौते के पहले चरण के लिए कानूनी समझौते पर मार्च के मध्य तक हस्ताक्षर हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि संयुक्त बयान के बाद एक विस्तृत कानूनी समझौता किया जाएगा। गोयल ने साथ ही बताया कि इस समझौते में किसी भी प्रकार के निवेश की प्रतिबद्धता नहीं है। वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने कहा कि एक बार बयान पर हस्ताक्षर हो जाने के बाद, यह एक कानूनी समझौते में तब्दील हो जाएगा और मार्च के मध्य तक, श्श्हमें उस कानूनी समझौते पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। कानूनी दस्तावेज पर हस्ताक्षर होने के बाद भारत कुछ अमेरिकी वस्तुओं पर शुल्क में कटौती करेगा।

संपत्ति का ब्योरा न देने पर रोका गया 47816 कर्मचारियों का वेतन, कर्मचारी परिषद ने जताई फैसले पर आपत्ति

लखनऊ ब्यूरो

लखनऊ। मानव संपदा पोर्टल पर चल–अचल संपत्ति का विवरण दर्ज न कराने के कारण प्रदेश के 47816 कर्मचारियों का जनवरी माह का वेतन रोक दिया गया है। इस पर राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने कड़ी आपत्ति जताई है। परिषद अध्यक्ष जेएन तिवारी ने मुख्य सचिव को पत्र लिखकर बताया कि तृतीय श्रेणी के 97 प्रतिशत और चतुर्थ श्रेणी के 94 प्रतिशत कर्मचारियों ने

विवरण भर दिया है, जबकि वरिष्ठ अधिकारी अब भी पीछे हैं। परिषद ने मांग की है कि निचले स्तर के कर्मचारियों का वेतन तुरंत जारी किया जाए। पोर्टल की प्रक्रिया को सरल बनाकर तकनीकी सहायता उपलब्ध कराई जाए ताकि सभी कर्मचारी आसानी से विवरण दर्ज कर सकें।

माध्यमिक के 1483 कार्मिकों का रोका गया वेतन

शासन के निर्देश के बाद भी माध्यमिक शिक्षा विभाग के 1483 कार्मिकों ने अपनी चल–अचल संपत्ति का ब्योरा निर्धारित पोर्टल पर नहीं दिया है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉ. महेंद्र देव ने इन कार्मिकों का वेतन न जारी करते हुए अनुशासनात्मक कार्यवाही के भी निर्देश दिए हैं। निदेशक ने कहा है कि शासन के निर्देश के बाद भी 31 जनवरी तक समूह ख के 48, समूह ग के 1189 व समूह घ के 246 कुल 1483 कार्मिकों ने मानव संपदा पोर्टल पर अपनी चल–अचल संपत्ति का ब्योरा नहीं दर्ज किया है।

उन्होंने इन सभी की सूची जारी करते हुए संबंधित अधिकारियों से कहा है कि अगर इनका वेतन जारी किया गया है तो संबंधित अधिकारी का उत्तरदायित्व तय करते हुए उनके खिलाफ कार्यवाही की जाए। इसके साथ ही संपत्ति का विवरण न देने वाले कार्मिकों के खिलाफ भी सक्षम स्तर से अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाए। इसकी सूचना निदेशालय को भी उपलब्ध कराई जाए।

आजमगढ़ के डीआईओएस हटाए गए

शासन ने आजमगढ़ के डीआईओएस उपेंद्र कुमार को हटा दिया है। उनकी जगह पर श्रावस्ती के बीएसए अजय कुमार को आजमगढ़ का डीआईओएस बनाया गया है। जानकारी के अनुसार आजमगढ़ के डीआईओएस पर गंभीर आरोप लगे थे। इसे लेकर उनके कार्यालय में हंगामा भी हुआ था। माध्यमिक शिक्षा विभाग के सचिव चंद्रभूषण सिंह की ओर से जारी आदेश के अनुसार उपेंद्र कुमार को सहायक शिक्षा निदेशक (भवन) मुख्यालय प्रयागराज भेजा गया है। उन्होंने कड़े निर्देश दिए हैं कि यह अधिकारी बिना नई तैनाती के तुरंत कार्यभार ग्रहण करेंगे। इतना ही नहीं उन्होंने बेसिक, माध्यमिक व एससीईआरटी के निदेशक को निर्देश दिया है कि वे इन्हें तुरंत कार्यमुक्त करेंगे। समय से कार्यमुक्त न करना अनुशासनहीनता मानी जाएगी। ऐसे कार्मिक के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी।

आशा–आशा संगिनी के बकाये का भुगतान करने के निर्देश

आशा व आशा संगिनी के लंबित देय के भुगतान को लेकर एनएचएम विभाग ने कड़े कदम उठाए हैं। मिशन निदेशक ने प्रदेश के सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को निर्देशित किया है कि 31 मार्च 2025 तक के सभी बकाया देय का भुगतान करें।

जिसकी उसकी रिपोर्ट एक सप्ताह के भीतर शासन को भेजें। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद की महामंत्री अरुणा शुक्ला ने बताया कि 24 जनवरी को 1090.95 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया था। आशा हेल्थ वर्कर्स एसोसिएशन की प्रदेश अध्यक्ष कुसुम लता यादव ने मिशन निदेशक व संयुक्त परिषद का आभार जताया।

सीमांत नगालैंड प्रादेशिक प्राधिकरण के लिए त्रिपक्षीय समझौता

अमित शाह बोले–केंद्र हर संभव मदद करेगा

दिल्ली ब्यूरो

नई दिल्ली। केंद्र ने नगालैंड सरकार और पूर्वी नगालैंड पीपुल्स ऑर्गनाइजेशन (ईएनपीओ) के साथ

राज्य के भीतर सीमांत नगालैंड प्रादेशिक प्राधिकरण के गठन के लिए त्रिपक्षीय समझौते पर बृहस्पतिवार को हस्ताक्षर किए। समझौता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में हुआ।

बाद में शाह ने कहा, केंद्र पूर्वी नागालैंड के विकास के लिए हर संभव मदद करेगा और अपनी सभी जिम्मेदारियों को पूरा करेगा। उन्होंने कहा, एक–दो को छोड़कर, अन्य सभी मुद्दे सुलझा लिए गए हैं। उन्होंने कहा, 2019 से हमने पूर्वोत्तर में 12 महत्वपूर्ण समझौते किए हैं। शाह ने कहा, मोदी सरकार की यह परंपरा रही है कि हम अपने द्वारा किए गए समझौतों को लागू करने के लिए हरसंभव प्रयास करते हैं। मैं ईएनपीओ के प्रतिनिधियों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि केंद्र सरकार पूर्वी नागालैंड के विकास के लिए भरपूर सहायता प्रदान करेगी और अपनी जिम्मेदारी भी निभाएगी। नगालैंड और केंद्र सरकार पर कोई संदेह नहीं होना चाहिए। हर राशि का निर्णय लेकर उसे जारी किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि आपकी संस्था की स्थापना के लिए प्रारंभिक खर्च केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा वहन किया जाएगा। राज्य के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने कहा, यह समझौता आपसी विश्वास को दर्शाता है, पूर्वी नागालैंड और पूरे राज्य की आकांक्षाओं को पूरा करता है, और विकास को हर घर तक पहुंचाने का प्रयास करता है। राज्य के छह पूर्वी जिलों में फैली आठ जनजातियों का प्रतिनिधित्व करने वाली सर्वोच्च संस्था, ईएनपीओ, दशकों की उपेक्षा का आरोप लगाते हुए 2010 से ही एक अलग राज्य की मांग कर रही है। बाद में इसने फ्रंटियर नागालैंड टेरिटोरियल अथॉरिटी (एफएनटीए) ढांचे के तहत एक निश्चित स्तर की स्वायत्तता के लिए केंद्र के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया।

मयाली बनेगा ग्लोबल टूरिज्म डेस्टिनेशन, मुख्यमंत्री साय ने 10 करोड़ की मयाली-बगीचा पर्यटन परियोजना का किया भूमिपूजन

एजेंसी

रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज भारत सरकार की स्वदेश दर्शन योजना 2.0 की उप–योजना सीबीडीडी के अंतर्गत स्वीकृत मयाली–बगीचा पर्यटन विकास परियोजना का मयाली नेचर कैंप में विधिवत भूमिपूजन किया। लगभग 10 करोड़ रुपये की लागत से क्रियान्वित इस परियोजना के तहत मयाली, विश्व प्रसिद्ध मधेश्वर पर्वत तथा बगीचा स्थित कैलाश गुफा क्षेत्र में आधुनिक पर्यटन सुविधाओं का विकास किया जाएगा। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि मयाली–बगीचा विकास परियोजना जशपुर जिले के लिए एक ऐतिहासिक पहल है। मयाली अब तेजी से पर्यटन मानचित्र पर उभर रहा है और आने वाले समय में इसे वैश्विक पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। इस परियोजना से क्षेत्र की प्राकृतिक, सांस्कृतिक और जनजातीय विरासत का संरक्षण होगा तथा समुदाय आधारित पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि मयाली की पहचान सदियों से मधेश्वर महादेव

से जुड़ी रही है, जिसे विश्व का सबसे बड़ा प्राकृतिक शिवलिंग माना जाता है। इस परियोजना के माध्यम से मधेश्वर पर्वत के धार्मिक और पर्यटन महत्व को राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय पहचान मिलेगी। परियोजना के अंतर्गत मयाली डेम के समीप पर्यटक रिसोर्ट और स्किल डेवलपमेंट सेंटर का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मयाली को एक समग्र इको–टूरिज्म और एडवेंचर डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जाएगा। यहां के जंगल, झरने, पहाड़ और समृद्ध आदिवासी संस्कृति को देश–दुनिया के पर्यटकों तक पहुंचाया जाएगा। पर्यटन से होने वाली आय का सीधा लाभ स्थानीय लोगों को मिलेगा। इसी उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा होम–स्टे नीति लागू की गई है।

संपादकीय

ममता बनर्जी का आसमान में सुराख करने का इरादा

न्यायालय में उपस्थित हुईं और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर में हो रही गड़बड़ियों के खिलाफ अपनी दलीलें पेश कीं। देश के इतिहास में यह पहली बार हुआ है जब किसी मुख्यमंत्री ने वकील की भूमिका भी निभाई है। सबसे खास बात यह कि ममता बनर्जी अपना या अपनी पार्टी का पक्ष रखने शीर्ष अदालत में प्रस्तुत नहीं हुईं बल्कि उन लाखों कमजोर लोगों का पक्ष रखने के लिए सामने आईं, जो एसआईआर से पीड़ित हैं, जिनके मताधिकार पर सरकारी कार्रवाई का चाबुक चला है। संक्षेप में कहें तो ममता बनर्जी लोकतंत्र को बचाने के लिए मुख्यमंत्री होते हुए भी वकील की भूमिका में आईं। अदालत में अपनी दलीलों को पेश करने के बाद आखिरी में माननीय न्यायाधीशों से उन्होंने यही कहा कि लोकतंत्र बचा लीजिए। गौरतलब है कि एसआईआर को लेकर देश भर में गरीब और कमजोर लोग चिंतित हैं कि उनका नाम कहीं मतदाता सूची से कट न जाए। पांच साल में एक दिन उन्हें मिलता है जब उन्हें उसी कतार में खड़े होने का मौका मिलता है, जिस कतार में समाज का धनाढ्य और प्रभावशाली तबका भी लगता है। वोट देने का अधिकार अमीर और गरीब हरेक के पास एक जैसा है। लेकिन एसआईआर के कारण इस अधिकार पर बड़ी चोट पड़ चुकी है। भाजपा और चुनाव आयोग जिसे धार्मिक शब्दावली की तरह मतदाता सूची का शुद्धिकरण कहते हैं, वह असल में अन्याय और असमानता को बढ़ावा देने वाला है। पिछले साल जून में सबसे पहले बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया शुरु हुई थी, जिसका व्यापक और तार्किक विरोध विपक्ष ने किया था। बिहार में इस पर महागठबंधन ने वोटर बचाओ यात्रा भी निकाली थी, जिसे बड़े पैमाने पर समर्थन मिला था। इस मामले में अदालत में याचिकाएं दाखिल हुईं। कायदे से ऐसे में एसआईआर को रोक कर फैसले का इंतजार किया जाना चाहिए था। लेकिन बिहार में यह पूरी भी हुई और करोड़ों नाम वोटर लिस्ट से कटे, उसके बाद चुनाव हुए और नतीजा सबके सामने है। जिन घुसपैठियों के नाम पर एसआईआर को तत्काल कराने की जरूरत बताई गई, उस पर अब सत्ता पक्ष या चुनाव आयोग कुछ नहीं कहता कि कितने विदेशी नागरिक बिहार में वोटर लिस्ट में थे। अब घुसपैठियों का यही लचर तर्क प.बंगाल में दिया जा रहा है। यहां तो अर्मत्य सेन जैसे प्रतिष्ठित नागरिक तक को चुनाव आयोग ने नोटिस भेज दिया, तो आम गरीब आदमी की बिसात ही क्या है। इसलिए ममता बनर्जी को बुधवार को अदालत में कहना पड़ा कि न्याय बंद दरवाजे के पीछे रो रहा है। बता दें कि भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के समक्ष ममता बनर्जी अपने वकीलों के साथ कोर्ट रूम नंबर एक में मौजूद रहीं। मंगलवार को मुख्यमंत्री बनर्जी के नाम पर एक गेट पास जारी किया गया था। मोस्तारी बानू और टीएमसी सांसदों डेरेक ओ श्ब्रायन और डोला सेन की दायर याचिकाओं पर सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल एम पंचोली की बेंच ने सुनवाई की। जिनमें ममता बनर्जी ने अपनी दलील पेश की। सुश्री बनर्जी ने अपनी बात रखने की इजाजत मांगी। उन्होंने कहा, श्सर, मुझे सिर्फ 5 मिनट दें।श सीजेआई ने कहा कि 15 मिनट लीजिए। फिर ममता बनर्जी ने भावुक होकर कहा, श्न्याय बंद कमरों के पीछे रो रहा है। हम कहीं से न्याय नहीं पा रहे। मैंने चुनाव आयोग को 6 बार पत्र लिखा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला।श ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग बंगाल को निशाना बना रहा है। उन्होंने कहा, श्यह चुनाव आयोग नहीं, व्हाट्सएप कमीशन है। एसआईआर को सिर्फ नाम हटाने का हथियार बनाया जा रहा है, न कि सही जांच का। उन्होंने 24 वर्षों के बाद लागू की गई इस तात्कालिकता पर भी चिंता जताई, जिसे फसल कटाई के मौसम और प्रवासन के चरम समय के दौरान तीन महीनों में जल्दबाजी में पूरा किया गया था, और इसके मानवीय नुकसान को भी दर्ज किया, जिनमें 100 से अधिक मौतें, बीएलओ सदस्यों की मौतें और बड़े पैमाने पर अस्पताल में भर्ती होना शामिल है। ममता ने बताया कि एसआईआर के पहले चरण में ही लगभग 58 लाख नामों को मृत घोषित कर दिया गया।कई महिलाओं के नाम हटाए गए, जिससे यह प्रक्रिया महिला विरोधी लग रही है। उन्होंने कहा कि शादी के बाद महिलाओं का सरनेम बदलने या ससुराल जाने पर इसे मिसमैच बताकर नाम काट दिए जा रहे हैं। काम की तलाश में दूसरे जगह जाने वालों को भी इसी तरह परेशान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि गरीब परिवारों के नाम बिना उचित प्रक्रिया के हटाए जा रहे हैं, जिन्हें बाद में श्तार्किक विसंगतिय या श्गलत मानचित्रणश्च जैसे अस्पष्ट बहाने देकर उचित ठहराया जाता है, जो न्यायालय के निर्देशों का स्पष्ट उल्लंघन है। उन्होंने आधार को वैध प्रमाण के रूप में स्वीकार करने के न्यायालय के आदेश का स्वागत करते हुए, प्रश्न उठाया कि केवल बंगाल को ही निवास प्रमाण पत्र या जाति प्रमाण पत्र जैसे अन्यत्र स्वीकार किए जाने वाले दस्तावेजों से वंचित क्यों किया जा रहा है।

राशिफल

मेष :– नई सफलताओं से खुद की क्षमताओं का ऐहशास होगा। जीविका क्षेत्र में अवरोधों से मन में निराशा संभव भौतिक आकांक्षाओं की पूर्ति में ब्यय की अपेक्षित है। सन्तत्ति एवं सन्तानोत्पत्ति के लिए प्रयास सार्थक होंगे।
बृषभः– शासन–सत्ता कें लोगों के साथ निकटता बढे.गी। नियोजित परिश्रम द्वारा कार्य सिद्धी के आसार बनेंगे। पुराने संबंधों से लाभ संभव। परिवारिक वातावरण सुखद व उत्साहपूर्ण होगा।
मिथुनः– कठिन एवं विषम परिस्थितियों के मध्य परिश्रम व लगन से प्रगति के ओर अग्रसर होंगे। समाजिक सक्रीयता से मान–प्रतिष्ठा में बृद्धि होगी। घरेलू दायित्वो के प्रति आपकी महत्ता बढे.गी।
कर्कः– कुछ भौतिक आकांक्षाएं अपनी सार्थकता हेतु मन को उद्वेलित करेंगी। निकटस्थ सम्बन्धों में भावनात्मक अपेक्षाएं कष्टकारी हो सकती है। तामसी व गैर कायरे पर आकर्षित मन पर अंकुश लगावें।
सिंहः– कुछ नई इच्छाएं बलवती होंगी। प्रयासरत् क्षेत्रों में संघर्ष संभव परन्तु निराशावादी बिचारों को मन में स्थान न दें। किसी बड़े आयोजन हेतु समुचित ब्यवस्था के लिए मन प्रयत्नशील होगा।
कन्याः– नकारात्मक चिन्ताओं को त्याग कर अपनी क्षमताओं पर भरोसा करें। नौकरी–पेशे में अधिकारियों व सहकर्मियों के सहयोग से वातावरण सुखद होगा। राजनैतिक क्षेत्र के ब्यक्तियों का सहयोग प्राप्त होगा।
तुलाः– किसी नयी दिशा में सकारात्मक सोच अवश्य रंग लाएगी। पुरानी घटनाओं के स्मरण से मन को कष्ट संभव। दुबिधाओं को त्याग कर सही व स्वच्छ योजनाओं पर केन्द्रित हों।
वृश्चिकः– कुछ महत्वपूर्ण जिम्मेदारियाँ मन पर प्रभावी होंगी। घरेलू कायरे में ब्यस्तता बढे.गी। परिजनों के सहयोग से मन उत्साहित होगा। हंसमुख स्वभाव से आस–पास वातावरण में प्रसन्नता बिखेरेंगे।
धनुः– सम्बन्धों में ब्यवहारकुशल बनें। समाजिक व मांगलिक कार्यक्रमों में आपकी भागीदारी संभव। कुछ महत्वपूर्ण प्रयत्न की सार्थकता आप में नए उत्साह का संचार करेगा।
मकरः– बिद्यार्थियों के लिए ग्रहों की अनुकूलता लाभप्रद होगी। कुछ महत्वाकांक्षी योजनाएं सार्थक होगी। नवीन आशाएं नवीन उत्साह लाएंगी। कार्य क्षेत्र में सम्बन्धों का भरपूर लाभ मिलेगा।
कुंभः– अन्तमरुखी स्वभाव को त्याग बहिरमुखी बनें। कुछ महत्वपूर्ण अभिलाषाओं की पूर्ति के आसार हैं। परिजनों के सुख–दुख के प्रति मन चिन्तित होगा। कार्य क्षेत्र में ब्यस्तता बढे.गी।
मीनः– पुरानी समस्याओं पर बिजय प्राप्त कर सुखद अनुभूति करेंगे। ग्रहों की अनुकूलता से कोई अवरोधित कार्य हल होने के आसार बनेंगे। समुचित परिश्रम करने में असमर्थ मन परेशान होगा।

सीमित संसार से असीमित कल्पना तक : बाल-पठन संस्कृति का संकट

–डॉ. सत्यवान सौरभ

एक समय ऐसा भी था, जब मुझे बाल–पत्रिकाओं के अस्तित्व की कोई जानकारी नहीं थी। यह जानना तो दूर, मुझे इस बात का आभास तक नहीं था कि विद्यालयी पाठ्यक्रम की पुस्तकों के अतिरिक्त भी बच्चों के लिए विशेष रूप से कुछ लिखा–पढ़ा जाता है। हमारे लिए पढ़ना केवल स्कूल से जुड़ी एक बाध्यता थीकृ होमवर्क, परीक्षा और अंकों तक सीमित। इसका एक बड़ा कारण यह भी था कि हमारे घर में न तो नियमित रूप से समाचार–पत्र आता था और न ही कोई पत्रिका। पढ़ना हमारे जीवन की संस्कृति नहीं, बल्कि मजबूरी था। फिर भी, यदि भीतर कहीं पढ़ने की रुचि ने जन्म लिया, तो उसका श्रेय पाठ्यपुस्तकों को नहीं, बल्कि कॉमिक्स को जाता है। बचपन में मैंने कॉमिक्स जी भरकर पढ़ीं। वे रंग–बिरंगे चित्र, छोटे–छोटे संवाद और घटनाओं की तेज़ गति मुझे एक ऐसी दुनिया में ले जाती थी, जहाँ कल्पना पर कोई रोक नहीं थी। पाठ्यक्रम की कहानियाँ और कविताएँ जहाँ अक्सर नैतिक उपदेशों में उलझी रहती थीं, वहीं कॉमिक्स सहजता से आनंद देती थीं। वे मुझे यह सिखाती थीं कि पढ़ना बोझ नहीं, उत्सव भी हो सकता है। कॉमिक्स ने मेरे भीतर पाठक का पहला बीज बोया। उस समय यह समझ नहीं थी कि यह कोई साहित्यिक यात्रा है, लेकिन आज पीछे मुड़कर देखने पर स्पष्ट होता है कि पढ़ने की आदत का पहला द्वार वहीं से खुला। यह अनुभव अकेला नहीं है। असंख्य बच्चों के लिए कॉमिक्स, पहेलियाँ और चित्र–कथाएँ ही पढ़ने की दुनिया में प्रवेश का पहला माध्यम रही हैं। मुझे आज भी हिसार रेलवे स्टेशन की वह घटना स्पष्ट रूप से याद है। प्लेटफॉर्म पर स्थित एक बड़े पुस्तक–स्टॉल पर मेरी नज़र ठहर गई थी। वहाँ सजी हुई सुंदर, चमकदार और आकर्षक किताबेंकृ विशेषकर बच्चों के लिएकृमेरे लिए किसी अजाने संसार का द्वार थीं। यह पहली बार था, जब मैंने किताबों को इतनी विविधता और भव्यता के साथ देखा। उस समय मैं उन्हें केवल देख पाया, खरीद नहीं सका, लेकिन वह दृश्य मेरे मन पर स्थायी रूप से अंकित हो गया। वह क्षण मेरे जीवन का एक मौन मोड़ था। उस दिन मेरे हाथ खाली थे, पर मन में एक सवाल जन्म ले चुका थाकृक्या किताबें केवल स्कूल तक ही सीमित हैं? क्या पढ़ने की दुनिया इससे कहीं बड़ी नहीं हो सकती? शायद उसी दिन मेरे भीतर एक ऐसा पाठक जन्म ले चुका था, जिसे अभी अपनी भाषा, अपनी दिशा और अपना मंच मिलना बाकी था। यहीं से "सीमित संसार से असीमित कल्पना" की यात्रा शुरू होती है। बचपन में हमारी दुनिया अक्सर उन्हीं कहानियों और कविताओं तक सीमित रहती है, जो पाठ्यपुस्तकों में दी जाती हैं। ये पाठ आवश्यक हैं, पर पर्याप्त नहीं। वे ज्ञान तो देते हैं, पर कल्पना को पंख कम देते हैं। बाल–पत्रिकाएँ, बाल–साहित्य और रचनात्मक पठन इसी कमी को पूरा करते हैं। वे बच्चों को केवल अच्छा विद्यार्थी नहीं, संवेदनशील मनुष्य बनने की दिशा में ले जाते हैं। दुर्भाग्य यह है कि आज बाल–पठन संस्कृति निरंतर हाशिये पर जा रही है। जिन बाल–पत्रिकाओं ने कभी पीढ़ियों को भाषा, संवेदना और सामाजिक चेतना दी, वे या तो बंद हो चुकी हैं या सीमित दायरे में सिमट गई हैं। इसका एक बड़ा कारण बदलती जीवन–शैली और डिजिटल माध्यमों का बढ़ता प्रभुत्व है। मोबाइल, टैबलेट और सोशल मीडिया ने बच्चों के हाथों से किताबें छीन ली हैं। यह कहना आसान है कि तकनीक ने पढ़ने की आदत खत्म कर दी, लेकिन सच यह है कि हमने स्वयं किताबों को बच्चों के जीवन से धीरे–धीरे बाहर कर दिया है। अभिभावक आज बच्चों को मोबाइल देना आसान समझते हैं, लेकिन किताब दिलाना अतिरिक्त

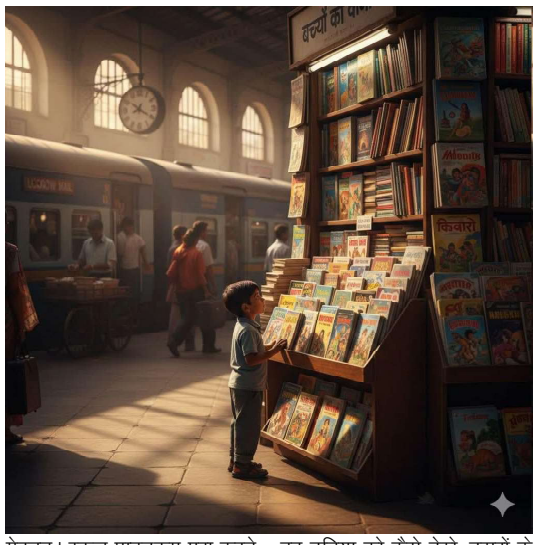

मेहनत। स्कूल पाठ्यक्रम पूरा करने की जल्दी में रचनात्मक पठन को गैर–ज़रूरी मान लिया गया है। परिणामस्वरूप, बच्चों की कल्पना या तो पाठ्यक्रम की सीमाओं में कैद है या फिर डिजिटल शोर में खो चुकी है। बाल–पठन संस्कृति किसी भी समाज की बौद्धिक और नैतिक नींव होती है। बाल–पत्रिकाएँ केवल मनोरंजन नहीं करतीं, वे भाषा गढ़ती हैं, प्रश्न पूछने की आदत डालती हैं और सामाजिक यथार्थ से परिचित कराती हैं। एक अच्छी बाल–कहानी बच्चे को यह सिखा सकती है कि वह दुनिया को कैसे देखे, दूसरों के दुःख को कैसे समझे और अपने विचार कैसे व्यक्त करे। आज आवश्यकता इस बात की है कि हम बाल–साहित्य को फिर से गंभीरता से लें। इसे केवल "बच्चों की चीज़" कहकर हल्के में न लें। बाल–पत्रिकाओं और बाल–पुस्तकों को स्कूलों, पुस्तकालयों और घरों में पुनः स्थान देना होगा। शिक्षक, अभिभावक और नीति–निर्माताकृसभी को यह समझना होगा कि पढ़ने की आदत बचपन में ही विकसित होती है। सरकारी और निजी स्तर पर ऐसे प्रयास होने चाहिए, जिनसे बाल–पत्रिकाएँ सुलभ हों। रेलवे स्टेशनों, बस अड्डों और सार्वजनिक स्थानों पर पुस्तक–स्टॉल केवल सजावट न बनें, बल्कि बच्चों के लिए पहुँच योग्य बनें। हर बच्चा उस स्टॉल पर खड़ा होकर केवल देखने तक सीमित न रह जाएकृयह हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। आज जब नई शिक्षा नीति रचनात्मकता और समग्र विकास की बात करती है, तब बाल–पठन संस्कृति को उसके केंद्र में रखना अनिवार्य है। पाठ्यपुस्तकों के साथ–साथ बाल–साहित्य को भी शिक्षा का अभिन्न हिस्सा बनाना होगा। क्योंकि पढ़ना केवल जानकारी अर्जित करना नहीं, बल्कि सोचने की कला सीखना है। अंततः, यह स्वीकार करना होगा कि कभी–कभी एक किताबकृजिसे बच्चा खरीद नहीं पातीकृवही उसके जीवन की दिशा तय कर देती है। हिसार रेलवे स्टेशन का वह पुस्तक–स्टॉल आज भी मेरे भीतर जीवित है। वह मुझे बार–बार याद दिलाता है कि सीमित संसाधनों के बीच भी असीमित कल्पनाएँ जन्म ले सकती हैंकृबस उन्हें सही समय पर सही किताब मिल जानी चाहिए।

जाति, न्याय और लोकतंत्र : एक असहज सच्चाई

–डॉ. प्रियंका सौरभ

भारत का लोकतंत्र केवल एक शासन प्रणाली नहीं, बल्कि एक नैतिक संकल्प हैकृसमानता, न्याय और बंधुत्व का। संविधान की प्रस्तावना इसी संकल्प का उद्घोष करती है। परंतु आज जब हम अपने चारों ओर देखते हैं, तो यह प्रश्न असहज रूप से सामने खड़ा होता है कि क्या हम उस संकल्प के साथ न्याय कर पा रहे हैं? या फिर लोकतंत्र का यह ढांचा भीतर से दरक चुका है, जहाँ कानून, व्यवस्था और सत्ताकृतीनों ही जाति, वर्ग और पहचान की गिरफ़्त में हैं। आज कानून बनते हैं, संशोधन होते हैं, नए–नए प्रावधान जोड़े जाते हैं, परंतु उनके पीछे की मंशा पर सवाल उठना स्वाभाविक हो गया है। क्या ये कानून नागरिक के लिए हैं, या किसी विशेष समूह, वर्ग या वोट बैंक के लिए? जब विधायन का आधार तर्क और न्याय की जगह सामाजिक पहचान लेने लगे, तब लोकतंत्र का संतुलन बिगड़ना तय है। कानून का काम समाज को जोड़ना है, लेकिन यदि वही समाज को खाँचों में बाँटने का माध्यम बन जाए, तो यह स्थिति केवल चिंताजनक नहीं, बल्कि खतरनाक भी है। न्याय व्यवस्था की भूमिका किसी भी लोकतंत्र में सबसे पवित्र मानी जाती है। न्यायालय वह स्थान है जहाँ अंतिम उम्मीद जाकर टिकती है। लेकिन जब यह धारणा बनने लगे कि न्याय की दहलीज़ पर पहुँचने से पहले व्यक्ति की जाति, हैसियत और राजनीतिक संरक्षण देखा जा रहा है, तो विश्वास की नींव हिलने लगती है। न्याय केवल निर्णय नहीं होता; वह भरोसा होता है। और जब यह भरोसा टूटता है, तो उसका असर केवल एक व्यक्ति पर नहीं, पूरे समाज पर पड़ता है। आज न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या, फैसलों में देरी, और कुछ मामलों में दिखता स्पष्ट या अप्रत्यक्ष पक्षपातकृये सब लोकतंत्र के स्वास्थ्य पर गंभीर प्रश्नचिह्न हैं। लोकतंत्र के नाम पर सत्य का क्षरण एक धीमी लेकिन निरंतर प्रक्रिया है। यह एक दिन में नहीं होता। पहले असुविधाजनक सवालों को 'राष्ट्र–विरोधी' कहा जाता है, फिर आलोचना को 'षड्यंत्र' बताया जाता है, और अंततः सच बोलने वालों को हाशिए पर धकेल दिया जाता है। जब संसद में बहसें समाधान से अधिक शोर बन जाएँ, जब मीडिया का एक बड़ा हिस्सा सत्ता का विस्तार बन जाए, और जब सामाजिक विमर्श भावनाओं के उकसावे तक सिमट

जाएकृतो समझ लेना चाहिए कि लोकतंत्र केवल औपचारिक रूप से जीवित है, उसकी आत्मा संकट में है। समरसता की बातें हर मंच से होती हैं, लेकिन ज़मीनी सच्चाई इसके उलट दिखाई देती है। समाज में विभाजन गहराता जा रहा हैकृधर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, भाषा और क्षेत्र के नाम पर। सत्ता इन विभाजनों को पाटने के बजाय, अक्सर इन्हें साधन की तरह इस्तेमाल करती है। 'फूट डालो और राज करो' अब इतिहास की किताबों में दर्ज कोई औपनिवेशिक नीति नहीं रही, बल्कि समकालीन राजनीति की एक प्रभावी रणनीति बन चुकी है। जब जनता आपस में उलझी रहती है, तब सत्ता से सवाल करने की ताक़त कमजोर पड़ जाती है। यह विडंबना ही है कि एक ओर जाति–पाति मिटाने की बातें होती हैं, दूसरी ओर हर राजनीतिक गणित जातिगत समीकरणों पर आधारित होता है। चुनावी टिकटों से लेकर नीतिगत फैसलों तक, जाति एक निर्णायक तत्व बनी हुई है। ऐसे में 'जाति से ऊपर उठने' का उपदेश खोखला प्रतीत होता है। यदि सचमुच जाति अप्रासंगिक होती, तो उसका उल्लेख हर नीति, हर बहस और हर चुनाव में इतनी प्रमुखता से क्यों होता? आशाओं के इस देश में निराशा का बढ़ता विस्तार केवल आर्थिक कारणों से नहीं है। बेरोज़गारी, महँगाई और संसाधनों की असमानता तो कारक हैं ही, लेकिन उससे भी बड़ा कारण हैकृविश्वास का टूटना। जनता ने जिन हाथों में सत्ता सौंपी, उनसे यह अपेक्षा थी कि वे सबके हित में काम करेंगे। परंतु जब वही सत्ता अपने अस्तित्व को बचाने के लिए समाज को बाँटने लगे, आलोचना से डरने लगे और असहमति को दबाने लगे, तब लोकतंत्र का नैतिक आधार कमजोर हो जाता है। सत्ता का सच से मुँह फेर लेना किसी भी समाज के लिए शुभ संकेत नहीं है। जब शासन केवल अपनी छवि गढ़ने में व्यस्त हो जाए और वास्तविक समस्याओं से आँख चुराने लगे, तब झूठ एक समानांतर यथार्थ रच देता है। इस यथार्थ में आँकड़े चमकदार होते हैं, भाषण ऊँचे होते हैं, लेकिन आम आदमी की ज़िंदगी लगातार कठिन होती जाती है। सच को ढँकने के लिए प्रचार का सहारा लिया जाता है, और धीरे–धीरे जनता को यही सिखाया जाता है कि सवाल करना असभ्यता है। विधान सभाओं और संसद में सामाजिक न्याय की बातें अक्सर सुनाई देती हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पर वही अन्याय नए–नए रूपों में सामने आता है। नीतियों में सुधार के नाम पर ऐसे प्रावधान लाए जाते हैं, जो या तो आधे–अधूरे होते हैं या फिर नए विवादों को जन्म देते हैं। यह स्थिति तब और गंभीर हो जाती है, जब नीति–निर्माण में प्रभावित वर्गों की वास्तविक भागीदारी न हो, और फैसले ऊपर से थोपे जाएँ। लोकतंत्र की असली परीक्षा संकट के समय होती है। क्या वह सबसे कमजोर नागरिक के साथ खड़ा होता है, या सबसे ताकतवर के साथ? आज यह प्रश्न पहले से अधिक प्रासंगिक है। जब अन्याय किसी 'दूसरे' के साथ होता है, तब समाज का एक बड़ा हिस्सा चुप रहता है। लेकिन यही चुप्पी कल अपने ही अधिकारों के क्षरण का कारण बनती है। चयनात्मक नैतिकताकृजहाँ हम केवल अपने हित का अन्याय देखते हैंकृलोकतंत्र को भीतर से खोखला कर देती है। यह संपादकीय किसी एक सरकार, एक दल या एक नेता के विरुद्ध आरोप–पत्र नहीं है। यह एक सामूहिक आत्मावलोकन का आग्रह है। लोकतंत्र केवल शासकों की जिम्मेदारी नहीं, नागरिकों की भी उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी है। सवाल पूछना, असहमति जताना और सच के साथ खड़ा होनाकृयही लोकतंत्र की असली शक्ति है। यदि हम सुविधा के लिए चुप रहना चुनते हैं, तो फिर व्यवस्था के पतन की जिम्मेदारी से भी हम बच नहीं सकते। आज आवश्यकता है कि न्याय को फिर से उसके मूल अर्थ में लौटाया जाएकृनिष्पक्ष, निर्भीक और समान। कानून का उद्देश्य सत्ता को सुरक्षित करना नहीं, बल्कि नागरिक के अधिकारों की रक्षा करना होना चाहिए। राजनीति का धर्म ध्रुवीकरण नहीं, समाधान होना चाहिए। और लोकतंत्र का अर्थ केवल पाँच साल में एक बार मतदान करना नहीं, बल्कि हर दिन सजग रहना होना चाहिए। यदि हम अब भी नहीं चेते, तो आने वाली पीढ़ियाँ हमसे यह नहीं पूछेंगी कि हमने किसे वोट दिया था, बल्कि यह पूछेंगी कि जब समाज बाँटा जा रहा था, जब न्याय पहचान पूछ रहा था, और जब सच को दबाया जा रहा थाकृतब हमने क्या किया। यही प्रश्न आज के भारत के लोकतंत्र के सामने सबसे बड़ा और सबसे जरूरी सवाल है।

डिजिटल दुनिया का अंधेरा पहलू : गाजियाबाद में ऑनलाइन गेमिंग तीन मासूम ज़िंदगियाँ छीनीं

–सुनील कुमार महला

हाल ही में उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में नाबालिग किशोरियां कोरियन गेम की लत का शिकार हो गई,यह बहुत ही दुखद घटना है।खेल के साथ जिंदगियां भी खत्म हो गईं। दरअसल,ऑनलाइन गेम का टास्क पूरा करने के लिए तीन बहनों ने नौवीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली,यह वास्तव में दिल दहलाने वाली घटना है। पाठकों को बताता चलूं कि गाजियाबाद में टीला मोड़ थाना इलाके में 3 फरवरी 2026 मंगलवार को ऑनलाइन कोरियन गेम श्लव गेमश रात का टास्क पूरा करने के लिए भारत सिटी सोसायटी की नौवीं मंजिल से तीन बहनों ने एक साथ छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। इस संबंध में पुलिस को किशोरियों के कमरे से आठ पेज का सुसाइड नोट और एक डायरी मिली है। पुलिस ने दोनों को कब्जे में ले लिया है। तीनों के कमरे की दीवार पर श्मेक मी ए हार्ट ऑफ ब्रोकनश लिखा हुआ मिला है। पुलिस ने बताया है कि फ्लैट की बालकानी से रात 2.15 बजे तीन बहनों ने छलांग लगाने की सूचना मिली थी। वास्तव में यह घटना एक ऑनलाइन गेम की लत और उस पर अत्यधिक निर्भरता से जुड़ी है। पुलिस ने यह पाया कि बच्चों को गेम खेलने से रोकने पर वे भावनात्मक रूप से टूट गए थे। बहरहाल,यह पहली बार नहीं है जब ऐसी घटना घटित हुई है।पहले भी ऑनलाइन गेम्स के कारण बच्चों/लोगों की जानें जा चुकी है। दूसरे शब्दों में कहें तो भारत में ऑनलाइन गेमिंग (ऑनलाइन वीडियो गेम्स और मोबाइल गेम्स) से जुड़ी लत, तनाव और वित्तीय/मनोवैज्ञानिक दबाव के कारण कई घटक परिणाम सामने आए हैं, जिनमें कुछ मौतें, आत्महत्याएं और जानलेवा घटनाएँ शामिल हैं। यहां पाठकों को बताता चलूं कि वर्ष 2016–17 में ऑनलाइन गेम ब्लू व्हेल के कारण लोगों की जान चली गई थी। यह भी एक ऑनलाइन चौलेंज था और इसमें भी टास्क पूरे करने होते थे। वास्तव में कुछ टास्क खतरनाक होते थे, जिसमें लोगों की जान चली जाती थी।इसी प्रकार से साल 2018 में किकी चौलेंज बच्चों की बीच लोकप्रिय हुआ। इस टास्क में लोग कार को धीरे–धीरे चलाते हुए उससे बाहर आते थे और डांस करते थे। इस टास्क में कई लोग घायल हुए। इतना ही नहीं, मोमो चौलेंज भी 2018 में ही वायरल हुआ था। इसमें एक यूजर मोमो बच्चों को परेशान करता है। इसमें भी टास्क पूरा करने के लिए कहा जाता है, जिसमें खुद को नुकसान पहुंचाना भी शामिल था। इसी प्रकार से साल 2019 में मध्य प्रदेश के नीमच में 16 वर्षीय लड़के ने खबरों के अनुसार लगभग 6 घंटे लगातार पब–जी गेम खेलते रहने के बाद कार्डियक अरेस्ट (हार्ट अटैक) से मौत हो गई थी।परिवार के अनुसार वह गेम में इतनी लीन हो गया था कि अचानक स्वास्थ्य बिगड़ गया।घ्युने में भी एक 27 वर्षीय युवक पब–जी खेलते समय अचानक गिर पड़ा और हृदयाघात/स्ट्रोक से उसकी मौत हुई। डॉक्टरों ने गेम की लत और मानसिक तनाव को एक कारण माना। मोबाइल गेम श्फ्री–फायरश की लत के कारण (मध्य प्रदेश) में एक किशोर ने फांसी लगाकर अपनी जान ले ली।इसी प्रकार से इंदौर में एक 13 वर्षीय बच्चे ने ऑनलाइन गेम में हार और पैसे कटने के डर से आत्महत्या की, क्योंकि उसे यह डर था कि माता–पिता इसके लिए उसे डांटेंगे।राजस्थान के श्रीगंगानगर में भी एक युवक ने लूडो/ऑनलाइन गेमिंग में हानि के बाद कर्ज और तनाव के कारण आत्महत्या कर ली।यही नहीं, हाल ही में भोपाल में एक चौदह वर्षीय छात्र ने भी मोबाइल गेमिंग की लत के चलते फांसी लगा ली थी। बहरहाल, यदि हम यहां पर सरल शब्दों में बात करें तो हाल की घटनाएं यह दिखाती हैं कि आज के बच्चे और युवा डिजिटल दुनिया में कितनी गहराई तक फंसते जा रहे हैं। वे एक साथ दो दुनिया में जी रहे हैं–एक असली(वास्तविक) और दूसरी मोबाइल–स्क्रीन वाली आभासी दुनिया या यूं कहें कि वर्चुअल दुनिया। गेम और सोशल मीडिया बुरे नहीं हैं, लेकिन जब यही किसी की पहचान, खुशी और सहारे का एकमात्र जरिया बन जाएं, तो समस्या खड़ी हो जाती है। बहरहाल , मीडिया में उपलब्ध जानकारी के अनुसार तीनों किशोरियां मोबाइल गेम की लत में थीं। पिता के रोकने पर उन्होंने यह कदम उठाया। हाल फिलहाल मामले की गहन जांच जारी है, लेकिन यह साफ है कि परिवार और बच्चों के बीच संवाद की कमी इस तरह की घटनाओं को जन्म देती है। आज कई परिवार या तो बच्चों की डिजिटल आदतों पर ध्यान नहीं देते, या फिर अचानक सख्ती दिखाने लगते हैं–लेकिन दोनों ही तरीके नुकसानदेह हैं। वास्तव में, यह समस्या सिर्फ एक परिवार या एक शहर तक सीमित नहीं है। झाबुआ और भोपाल की घटनाएं भी बताती हैं कि सोशल मीडिया और रील्स की लत रिश्तों और संवेदनाओं पर भारी पड़ रही है। जब रोक–टोक होती है, तो टकराव पैदा होता है, और वही टकराव कभी आत्महत्या तो कभी हिंसा का रूप ले लेता है।असल सवाल यही है कि क्या हम ऐसा समाज बना रहे हैं, जहां मोबाइल की दुनिया इंसानी रिश्तों से ज्यादा ताकतवर हो गई है। इस संकट से बचने का रास्ता सख्ती नहीं, बल्कि समझ, संवाद और संतुलन है–ताकि बच्चे स्क्रीन के नहीं, जीवन के साथ जुड़े रहें। दूसरे शब्दों में कहें तो ऑनलाइन गेमिंग की बढ़ती लत पर नियंत्रण के लिए माता–पिता और सरकार दोनों की अहम भूमिका है।माता–पिता को यह चाहिए कि वे अपने बच्चों के स्क्रीन टाइम की स्पष्ट सीमा तय करें और मोबाइल–इंटरनेट के उपयोग पर निगरानी रखें।घर में खेल–कूद, पढ़ाई और रचनात्मक गतिविधियों को बढ़ावा देकर बच्चों का ध्यान वैकल्पिक दिशा में मोड़ा जा सकता है।सच तो यह है कि बच्चे मिट्टी के घड़े होते हैं, जिन्हें कुम्हार की तरह सही हाथों से मनचाहा आकार दिया जा सकता है।माता–पिता और शिक्षक उस कुम्हार की भूमिका निभाते हैं, जिनका स्पर्श बच्चों का भविष्य गढ़ता है। वास्तव में सच तो यह है कि जैसी सोच, संस्कार और व्यवहार बच्चों को मिलते हैं, वे वैसे ही ढलते चले जाते हैं।प्रेम और धैर्य से दिया गया मार्गदर्शन उन्हें मजबूत बनाता है।डांट–फटकार की जगह समझ और संवाद उन्हें बेहतर इंसान बनाते हैं।अच्छे मूल्य बच्चों में आत्मविश्वास की नींव रखते हैं।गलत संगति या उपेक्षा उस कच्ची मिट्टी को बिगाड़ सकती है।इसलिए बचपन में दिया गया संस्कार जीवन भर साथ निभाता है।हर बच्चा अनोखा घड़ा है, जिसे अलग समझ की जरूरत होती है।समझदारी भरे हाथों में ही सुंदर और टिकाऊ व्यक्तित्व आकार लेता है। इसलिए इस क्रम में बच्चों से लगातार /सतत संवाद बनाए रखना और उन्हें ऑनलाइन खतरों के प्रति जागरूक करना भी जरूरी है।सरकार को भी यह चाहिए कि सरकार उम्र–आधारित नियमों के साथ सख्त कानून बनाए। होना तो यह चाहिए कि ऑनलाइन गेम्स में समय और खर्च की सीमा तय हो।स्कूलों में डिजिटल साक्षरता और काउंसलिंग कार्यक्रम शुरू किए जा सकते हैं।अवैध और सट्टानुमा गेमिंग ऐप्स पर सख्ती से रोक लगाये जाने की आवश्यकता महत्ती है।

अब किसानों को 5 मिनट में ई-केसीसी से ऋण- योगी

मुख्यमंत्री ने किया ऋण संगोष्ठी एवं राज्य फोकस पेपर 2026-27 का विमोचन

डिजिटल गवर्नेंस से किसानों को राहत, एफपीओ, सहकारिता व एमएसएमई से मजबूत हुई उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था

लखनऊ ब्यूरो

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि डिजिटल गवर्नेंस ने उत्तर प्रदेश में ऋण स्वीकृति की तस्वीर बदल दी है। अन्नदाता किसान जब पहले किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी के माध्यम से ऋण लेने जाता था, तो 25 दिन से लेकर एक महीने तक इंतजार करना पड़ता था लेकिन आज वही किसान ई–केसीसी के माध्यम से मात्र पांच मिनट में ऋण सुविधा प्राप्त कर रहा है। 2026–27 के लिए जो हमारा कृषि ऋण 3 लाख करोड़ है, यह पहले की तुलना में 13 फीसदी बढ़ा है। यही सुशासन है और इसी दिशा में हमें और मजबूती से आगे बढ़ना होगा।मुख्यमंत्री गुरुवार को लोकभवन में राज्य ऋण संगोष्ठी एवं राज्य फोकस पेपर 2026–27 के विमोचन के अवसर पर संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आज सरकार और अन्नदाता किसान मिलकर सोच रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई का उपयोग खेती में कैसे किया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से केंद्रीय बजट में एआई एग्रीकल्चर प्लेटफॉर्म की घोषणा की गई है और उत्तर प्रदेश इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कई एफपीओ फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गनाइजेशन को मंच पर सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि संगोष्ठी में जो मॉडल प्रस्तुत किए गए, वे पूरे प्रदेश के लिए प्रेरणा हैं। दिव्यांगजनों द्वारा संचालित कसया मिल्क प्रोड्यूसर एफपीओ, जिसमें 1,005 सदस्य हैं, इसका जीवंत उदाहरण है। पूर्वी उत्तर प्रदेश जैसे क्षेत्रों में, जिन्हें पहले कमजोर माना जाता था, दिव्यांगजनों ने अपनी मेहनत और क्षमता से नया उदाहरण प्रस्तुत किया है। यह आंखें खोलने वाला काम है और इसके लिए वे सभी अभिनंदन के पात्र हैं। मुख्यमंत्री ने मथुरा की 750 महिलाओं वाली सरसों उत्पादन कंपनी का उल्लेख करते हुए कहा कि मैंने स्वयं उनकी प्रदर्शनी देखी है। किस तरह मस्टर्ड ऑयल को प्रोसेसिंग से जोड़कर महिलाओं ने बेहतर मुनाफा कमाया, यह पूरे प्रदेश के लिए सीख है। सरकार इस तरह के प्रयासों को हर स्तर पर सहयोग देगी। सहकारिता क्षेत्र भी बदल रहा है। "सहकार से समृद्धि की ओर" के विजन के तहत डिजिटलीकरण, ई–गवर्नेंस और पारदर्शी नीतियों से सहकारी संस्थाओं में सुशासन और जवाबदेही सुनिश्चित हुई है। उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है, जो विश्व बैंक के साथ एग्री–टेक के क्षेत्र में काम कर रहा है। कृषि, एमएसएमई, महिला, एग्री–टेक और युवा उद्यमिता आज सरकार की प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री

ने 2017 से पहले की स्थिति को याद करते हुए कहा कि सहकारिता क्षेत्र में माफिया हावी था। रिजर्व बैंक ने 16 जिला सरकारी बैंकों को डिफाल्टर घोषित कर बंदी आदेश कर दिया था। हमारी सरकार में इन्हीं 16 में से 15 बैंक प्रॉफिट में आ चुके हैं और 16वें को भी प्रॉफिट में लाया जा रहा है। एमएसएमई सेक्टर में एक समय ऐसा था, जब उत्तर प्रदेश से बड़े पैमाने पर पलायन हो चुका था। हस्तशिल्प और निर्यात लगभग ठप थे और एमएसएमई सेक्टर बंदी की कगार पर खड़ा था। हमारी सरकार ने इसे एक जिला–एक उत्पाद ओडीओपी के रूप में आगे बढ़ाया। आज उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है, जो एमएसएमई सेक्टर को ६5 लाख का सुरक्षा बीमा दे रहा है। आज प्रदेश में 96 लाख एमएसएमई यूनिट्स कार्यरत हैं और लगभग 3 करोड़ परिवार इसी सेक्टर पर निर्भर हैं। टेक्नोलॉजी, मार्केट, पैकेजिंग , डिजाइनिंग से जोड़कर ओडीओपी को एक ब्रांड बनाया गया है। परिणाम यह है कि प्रदेश का निर्यात 84 हजार करोड़ से बढ़कर 1.86 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचा है। प्रधानमंत्री जब विदेश जाते हैं, तो राष्ट्राध्यक्षों को ओडीओपी प्रोडक्ट्स उपहार में देते हैं।उत्तर प्रदेश के एफपीओज की ताकत को रेखांकित करते हुए मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो का जिक्र किया। ग्रेटर नोएडा में आयोजित इस ट्रेड शो में सबसे बेहतरीन प्रदर्शन एफपीओ और फूड प्रोसेसिंग सेक्टर का रहा। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश का क्रेडिट–डेबिट रेशियो सीडी रेशियो 9 वर्षों में 43 प्रतिशत से बढ़कर 61 प्रतिशत हो गया है। लक्ष्य है कि इसी साल 31 मार्च तक इसे 62 प्रतिशत और 2026–27 में 65 प्रतिशत तक पहुंचाया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में लघु और सीमांत किसानों को सशक्त करने के लिए सहकारिता के माध्यम से ठोस कदम उठाए गए हैं। पहले किसानों को 11 प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण मिलता था, जिससे किसानों पर बोझ पड़ता था और बैंक भी घाटे में थे, क्योंकि उनका पैसा डूब जाता था। हमारी सरकार ने स्पष्ट निर्देश दिए कि लघु ,सीमांत किसानों को 5 से 6 प्रतिशत की ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाए, शेष सहयोग सरकार करेगी। किसानों को आसान ब्याज दर और सरल किस्तों पर ऋण मिलेगा तो वे खेती में निवेश करेंगे, तकनीक अपनाएंगे और उनकी आय में स्वाभाविक रूप से वृद्धि होगी। यूपी देश ही नहीं दुनिया का पहला राज्य है, जहां 86 प्रतिशत भूमि सिंचित है। 16 लाख ट्यूबवेल को मुफ्त बिजली दी जा रही है, नहरों से सिंचाई मुफ्त है और एक लाख किसानों को सोलर पैनल दिए जा चुके हैं। एक समय उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य कहा जाता था, लेकिन आज वही उत्तर प्रदेश देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने वाला राज्य बन चुका है। 10 वर्ष पहले देश की अर्थव्यवस्था में उत्तर प्रदेश का योगदान मात्र 8 प्रतिशत था, जबकि आज यह बढ़कर 9.5 प्रतिशत तक पहुंच चुका है। 2016 में उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था11.7 लाख करोड़ रुपये की थी, जो इस वित्तीय वर्ष में 31 मार्च तक बढ़कर 36 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचेगी। यह परिवर्तन अपने आप में एक बड़ा ब्रेकथ्रू है। उत्तर प्रदेश अब केवल रेवेन्यू सरप्लस स्टेट ही नहीं है, बल्कि बेहतर वित्तीय प्रबंधन का उदाहरण बन चुका है। 2016 में यूपी में प्रति व्यक्ति आय 43 हजार थी, जो आज बढ़कर 1.20 लाख हो चुकी है। हमारा फिस्कल डेफिसिट 3 प्रतिशत से भी कम है। कई वर्षों से प्रदेश ने कोई नया टैक्स नहीं लगाया है। देश में डीजल–पेट्रोल सबसे कम दाम पर यूपी में मिलता है। कृषि विकास दर 8 प्रतिशत से बढ़कर 18 प्रतिशत से अधिक हो गई है। देश की आबदी का 17 प्रतिशत हिस्सा यूपी में निवास करता है, लेकिन कृषि योग्य भूमि मात्र 11 प्रतिशत है। इसके बावजूद हमारा अन्नदाता किसान भारत के कुल खाद्यान्न उत्पादन का 21 फीसदी उत्पादन कर रहा है। एथेनॉल व चीनी उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश में नंबर एक है। 2000 से 2017 के बीच यानी 17 सालों में प्रदेश के गन्ना किसानों को मात्र 2 लाख 14 हजार करोड़ का भुगतान किया गया, जबकि हमने पिछले नौ वर्षों में ही किसानों के खाते में 3 लाख करोड़ रुपये का भुगतान किया है, यानि 86 हजार करोड़ ज्यादा। आज यूपी नंबर 8 से उठकर देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरकर सामने आया है।मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैंकरों से अपील करते हुए कहा कि वे ऋण वितरण में शर्तों को यथासंभव सरल करें और सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ किसानों, एफपीओ, एमएसएमई, सहकारिता से जुड़े लोगों को सहयोग दें। सिर्फ नीति बनाना पर्याप्त नहीं है, जमीन पर उसका असर दिखना चाहिए। इसके लिए जरूरी है कि छोटे–छोटे समूह बनाकर लक्षित प्रशिक्षण दिया जाए, मास्टर ट्रेनर्स तैयार किए जाएं और उन्हें सीधे उन लोगों के बीच भेजा जाए, जो एफपीओ, एमएसएमई, सर्विस सेक्टर, लखपति दीदी के लिए प्रस्तावित शी–मार्ट मॉडल या सहकारी संस्थाओं के माध्यम से आगे बढ़ना चाहते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि बैंक, नाबार्ड और अन्य वित्तीय संस्थान अगर ट्रेनिंग और क्रेडिट को साथ लेकर चलें, तो प्रदेश में रोजगार, आय और आत्मनिर्भरता की रफ्तार कई गुना तेज हो सकती है। तकनीक, ट्रेनिंग और वैल्यू एडिशन के जरिए उत्तर प्रदेश अपने अनलिमिटेड पोटेंशियल को साकार कर रहा है और यही प्रयास प्रदेश को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। इस अवसर पर प्रदेश सरकार में वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना, कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, नाबार्ड के महाप्रबंधक पंकज कुमार और रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय महाप्रबंधक पंकज कुमार उपस्थित रहे।

भाषा विश्वविद्यालय लखनऊ में दो दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सेमिनार का हुआ शुभारंभ

लखनऊ ब्यूरो

लखनऊ। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय, लखनऊ में "तीसरे लिंग की हाशिए से मुख्यधारा तक की यात्रा" विषय पर दो दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सेमिनार का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन कुलपति प्रो. अजय तनेजा ने किया। स्वागत भाषण विधि विभागाध्यक्ष डॉ. पीयूष त्रिवेदी ने प्रस्तुत किया। मुख्य अतिथि के रूप में किन्नर समाज की वरिष्ठ नेतृत्वकर्ता एवं उज्जैन पीठ जूना अखाड़ा की महामंडलेश्वर मां पवित्रा उपस्थित रहीं। उन्होंने विश्वविद्यालय द्वारा थर्ड जेंडर विषय पर सेमिनार आयोजित किए जाने की सराहना करते हुए समाज में सकारात्मक सोच विकसित करने की अपील की। मुख्य वक्ता साहित्यकार एवं आकाशवाणी गोरखपुर की पूर्व निदेशक डॉ. नीरजा माधव रहीं। उन्होंने अपने उपन्यास मुख्ता यमदीप सहित अन्य साहित्यिक कृतियों के माध्यम से तृतीय लिंग से जुड़े सामाजिक मुद्दों पर प्रकाश डाला। विशिष्ट अतिथि के रूप में फिनलैंड के डेवऑप्स इंजीनियर एवं पर्वतारोही अवनीश चंदेल उपस्थित रहे। वहीं विशेष अतिथि के रूप में भटिंडा केंद्रीय विश्वविद्यालय के विधि संकाय अध्यक्ष प्रो. दीपक सिंह तथा बाबा भीमराव अंबेडकर केंद्रीय विश्वविद्यालय की मानवाधिकार विभागाध्यक्ष प्रो. प्रीति मिश्रा ने भी विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम के अंत में सह–समन्वयक एवं असिस्टेंट प्रोफेसर अंशुल पांडेय ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों तथा भारत सरकार द्वारा तृतीय लिंग के हित में किए गए प्रयासों पर प्रकाश डालते हुए सभी अतिथियों का आभार प्रकट किया। कार्यक्रम का संचालन एलएलएम छात्र अमन कुमार त्रिपाठी एवं अस्मिता मिश्रा ने किया। इस अवसर पर कुलानुशासक डॉ. नीरज शुक्ला, विधि संकाय अध्यक्ष प्रो. मसूद आलम, समन्वयक डॉ. श्वेता त्रिवेदी सहित बड़ी संख्या में शिक्षक एवं छात्र–छात्राएं उपस्थित रहे।

2017 के बाद गन्ना किसानों को तीन लाख करोड़ का भुगतान : सीएम योगी

संवाददाता

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वर्ष 2017 के बाद प्रदेश में गन्ना किसानों की स्थिति में ऐतिहासिक सुधार हुआ है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2000 से 2017 के बीच 17 वर्षों में गन्ना किसानों को कुल 2.14 लाख करोड़ रुपये का भुगतान किया गया, जबकि वर्ष 2017 से 2025 के बीच केवल 8–9 वर्षों में 3 लाख करोड़ रुपये सीधे किसानों के खातों में भेजे गए हैं। मुख्यमंत्री योगी यह बातें राज्य ऋण संगोष्ठी एवं राज्य फोकस पेपर 2026–27 के विमोचन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि आधे समय से भी कम अवधि में पिछली सरकारों की तुलना में 86 हजार करोड़ रुपये अधिक भुगतान गन्ना किसानों को किया गया है। योगी ने कहा कि वर्तमान में प्रदेश सरकार गन्ना किसानों को 400 रुपये प्रति क्विंटल का भुगतान कर रही है। यह सरकार की किसान हितैषी नीतियों और ठोस निर्णयों का परिणाम है, जिससे अन्नदाता किसानों को सीधा लाभ मिला है। सीएम योगी ने बताया कि उत्तर प्रदेश आज इथेनॉल उत्पादन में देश में पहले स्थान पर है। इसके साथ ही देश के कुल गन्ना उत्पादन का 55 प्रतिशत हिस्सा अकेले उत्तर प्रदेश से आता है। चीनी उत्पादन में भी यूपी देश में शीर्ष स्थान पर बना हुआ है। उन्होंने कहा कि गन्ना आधारित अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए सरकार ने समयबद्ध भुगतान, निवेश को बढ़ावा और उद्योगों के आधुनिकीकरण जैसे कई कदम उठाए हैं, जिसका सीधा लाभ किसानों और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मिल रहा है।

इकलौते बेटे के जनाजे से लिपटकर रोई मां, चाइनीज मांझे से गई जान

संवाददाता

लखनऊ। राजधानी लखनऊ में चाइनीज मांझे की वजह से जान गंवाने वाले शोएब का जनाजा गुरुवार को उठा। घर के इकलौते बेटे की लाश देखने के बाद बूढ़ी मां बदहवास हैं। पत्नी का रोते–रोते बेहोश हो जा रही थी। सुध–बुध खो बैठी पत्नी होश में आने पर बस इतना ही कह पा रही थी कि देखो, सोते हुए कितने स्मार्ट लग रहे हैं। कोई इन्हें उठाओ। पत्नी की बात चीख सुनकर मौजूद हर किसी की आंखें नम हो जा रही थी। दुबग्गा के शीते विहार कॉलोनी में शोएब का घर है। 4 फरवरी को चाइनीज मांझे से गर्दन कटने से उनकी मौत हो गई थी। गुरुवार सुबह पोस्टमॉर्टम के बाद उनका शव घर पहुंचा। घर पर रिश्तेदार–पड़ोसियों की भीड़ लगी थी। शोएब की 2 बेटियां हैं। बड़ी बेटी 6 साल की है। पापा का शव देखकर वह भी रोए जा रही थी। जबकि 2 वर्षीय छोटी बेटी घर में अचानक से लोगों की भीड़ और सफेद कपड़े में लपेटकर रखे पापा को निहार रही थी। पड़ोसी बताते हैं कि शोएब ने 5 महीने पहले एक घर खरीदा था। उसका रेनोवेशन कराकर परिवार के साथ रह रहे थे। वह अपनी बेटियों को खूब पढ़ाना चाहते

थे। चाहते थे कि दोनों बेटियां अफसर और डॉक्टर बनें। दो मंजिले घर के ग्राउंड फ्लोर पर बाहर के कमरे में शोएब का शव रखा गया। शव के पास खड़ी पत्नी और मां रो–रोकर बदहवास थीं। पति के शव को देखकर पत्नी महिलाओं से रोते हुए कह रही थी–सो रहे हैं, कोई इनको उठाओ। पत्नी की बात सुनकर ढांढ़स बंधा रही महिलाएं भी अपने आंसू नहीं रोक पा रही थीं। वह कहे जा रही थी३देखो सोते हुए कितने स्मार्ट लग रहे। मां को कई लोग संभालने में लगे थे। बहनोई अफसर खां के अनुसार, शोएब के पिता की 8 साल पहले मौत हो गई थी। घर में 75 साल की बुजुर्ग मां हैं। पत्नी और दो बच्चे हैं। एक बेटी 2 साल की है। वह अब भी गोद में खेलती है। सबकी जिम्मेदारी शोएब पर ही थी। इसको लेकर वह योजनाएं बनाता था। वह अक्सर बोलता था कि दोनों बेटियों को खूब पढ़ाऊंगा३अच्छा अफसर, डॉक्टर बनाऊंगा। उनके भविष्य को सिक्योर करने के लिए वह घर बनवा रहा था। इसे किराये पर उठाने का प्लान था। शोएब के बड़े साढ़ू रेहान ने बताया कि शोएब छोटे भाई जैसा था। आज मेरी छोटी बहन जैसी साली चाइनीज मांझे की वजह से विधवा हो गई है। शोएब बाइक से जा रहे थे। हैदरगंज ओवरब्रिज पर चाइनीज मांझा फंसा हुआ था। मांझा दिखा नहीं और सीधे शोएब की गर्दन से लग गया। उनकी गर्दन से खून निकलने लगा। वह वहीं गिरकर तड़पने लगे। न जाने और कितनी बहनें इसकी वजह से विधवा हो जाएंगी। इस पर पूरी तरह से रोक लगनी चाहिए। घर का इकलौता लड़का था। पूरे इलाके में सबका प्यारा था। सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इसको बेचने वालों को तत्काल सजा होनी चाहिए।

बैंक अफसर पत्नी ने लगाया दहेज उत्पीड़न का आरोप, पति, सास और जेठ पर मारपीट कर घर से निकालने की एफआईआर

संवाददाता

लखनऊ। राजधानी के पारा थाना क्षेत्र से दहेज उत्पीड़न और घरेलू हिंसा का एक गंभीर मामला सामने आया है। एक बैंक में डिप्टी मैनेजर के पद पर कार्यरत महिला ने अपने पति, सास, जेठ और एक सहयोगी पर दहेज की मांग, मानसिक व शारीरिक प्रताड़ना, गाली–गलौज और घर से निकालने का आरोप लगाया है। पीड़िता ने थाना पारा में लिखित तहरीर देकर एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। पीड़िता श्रुति मिश्रा का विवाह 2 मार्च 2025 को पारा स्थित के. सन्स लॉन में हिंदू रीति–रिवाज से आशुतोष तिवारी से हुआ था। आरोप है कि विवाह के समय पीड़िता के पिता ने मांग पर 10 लाख रुपए नकद दहेज दिया था। इसके बावजूद ससुराल पक्ष संतुष्ट नहीं हुआ और अतिरिक्त दहेज की मांग करता रहा। तहरीर के अनुसार, शादी के दूसरे ही दिन सास शोभा तिवारी ने पीड़िता के पिता को अपशब्द कहे और दहेज के सामान को घटिया बताया।

दो साल में कैसे लापता हो गए एक लाख लोग! हाईकोर्ट में गृह सचिव और डीजीपी को किया तलब

संवाददाता

लखनऊ। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने उत्तर प्रदेश में गुमशुदा व्यक्तियों के संबंध में दर्ज स्वतः संज्ञान याचिका पर गुरुवार को सुनवाई की। न्यायालय ने इस मामले के संबंध में राज्य सरकार के संबंधित विभागों के पास उपलब्ध सभी आंकड़ों और रिकॉर्ड को तलब किया है। अगली सुनवाई के लिए 23 मार्च की तिथि नियत करते हुए, अपर मुख्य सचिव गृह तथा पुलिस महानिदेशक को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा सुनवाई के समय उपस्थित रहने का भी आदेश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति राजन राय और न्यायमूर्ति एके चौधरी की खंडपीठ ने उक्त मामले में दर्ज स्वतः संज्ञान जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए पारित किया। उल्लेखनीय है कि एक गुमशुदा व्यक्ति से संबंधित मामले की सुनवाई के दौरान न्यायालय के संज्ञान में आया कि यूपी में पिछले लगभग दो साल में 1,08,300 लोग लापता हो चुके हैं, जिनके संबंध में गुमाशुदगी रिपोर्ट दर्ज हैं। इनमें से मात्र 9700 लोगों का पुलिस पता लगा सकी है। न्यायालय ने इस स्थिति को बेहद चिंताजनक और गंभीर करार देते हुए, मामले को 'प्रदेश में गुमशुदा व्यक्तियों के संबंध में' शीर्षक से जनहित याचिका दर्ज करने का आदेश दिया था। अब आगामी 23 मार्च को इस मामले में फिर से सुनवाई होगी।

संक्षिप्त

नगर निगम ने सील किया गल्ला मंडी का खाता, 64 लाख टैक्स बकाया

संवाददाता

लखनऊ। लखनऊ नगर निगम ने जोन–6 स्थित नवीन गल्ला मंडी, सीतापुर रोड पर बड़ी कार्रवाई करते हुए बैंक खाता सील कर दिया है। कुल 64 लाख 94,040 रुपए गल्ला मंडी पर हाउस टैक्स बकाया था। इसमें से एक प्रॉपर्टी का किराया 22 लाख 57 हजार 922 रुपए था। गल्ला मंडी अधिकारियों ने नगर निगम को चेक बिना साइन के व्हाट्सऐप पर भेज दिया था। उसे नगर निगम में जमा नहीं किया गया। अपर नगर आयुक्त डॉ. अरविंद कुमार राव ने बताया कि लंबे समय से बकाया प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली न होने पर मंडी समिति के बैंक खाते को सीज कर दिया गया है। नगर निगम अधिकारियों ने बताया कि नवीन गल्ला मंडी सीतापुर रोड, लखनऊ के भवन संख्या जीबी, सीसी पर 31 मार्च 2026 तक कुल 42 लाख 36 हजार 118 रुपए प्रॉपर्टी टैक्स बकाया था। मंडी से जुड़े प्रॉपर्टी नंबर 605/385 पर 22 लाख 57 हजार 922 रुपए की राशि बकाया है। नगर निगम द्वारा का कहना है कि प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली के लिए पहले भी संबंधित संस्था को कई बार बिल एवं नोटिस जारी किए गए थे। अधिकारियों द्वारा व्यक्तिगत रूप से संपर्क कर बकाया राशि जमा करने के लिए भी कहा गया।

महापौर ने मृतक आश्रितों को सौंपे ज्वाइनिंग लेटर, 13 लोगों को मिली नौकरी

संवाददाता

लखनऊ। नगर निगम लखनऊ मुख्यालय में गुरुवार को महापौर सुषमा खर्कवाल ने मृतक आश्रितों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। यह कार्यक्रम उन परिवारों के लिए राहत का संदेश लेकर आया, जिन्होंने अपने परिजनों को सेवा के दौरान खो दिया था। कार्यक्रम के दौरान महापौर सुषमा खर्कवाल ने कुल 13 मृतक आश्रितों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। इनमें शेखर, रागिनी, विकास भारती, बीनू रितिक गहरवाल,अवनीश कुमार, पिन्की, आकाश कुमार भारती, सुभाष धानुक,नीरज कुमार, शिवांशू भारती,काजल और शिवम भारती शामिल हैं। इन सभी मृतक आश्रितों को सफाई कर्मी के पद पर नियुक्त किया गया है। महापौर ने नवनियुक्त कर्मचारियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि नगर निगम अपने कर्मचारियों और उनके परिवारों के

प्रति संवेदनशील है। उन्होंने कहा कि मृतक आश्रितों को नौकरी देना केवल एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि पीड़ित परिवारों को सम्मान और आत्मनिर्भरता प्रदान करने का माध्यम है। महापौर ने सभी नवनियुक्त कर्मियों से ईमानदारी और निष्ठा के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करने का आह्वान किया। अपर नगर आयुक्त ललित कुमार ने बताया कि मृतक आश्रितों की नियुक्ति प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी और नियमों के अनुरूप पूरा किया गया है। इस पहल से न केवल प्रभावित परिवारों को आर्थिक सहारा मिलेगा, बल्कि नगर निगम की सफाई व्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। कार्यक्रम के अंत में सभी नवनियुक्त कर्मचारियों ने महापौर नगर निगम प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में नगर स्वास्थ्य अधिकारी पीके श्रीवास्तव, प्रभारी अधिकारी अधिष्ठान विकास सिंह सहित नगर निगम के अन्य वरिष्ठ अधिकारी एवं कर्मचारीगण उपस्थित रहे। मौके पर अधिकारियों ने नवनियुक्त कर्मचारियों को विभागीय नियमों और कार्य जिम्मेदारियों की जानकारी भी दी।

दुबग्गा में खुले नाले में 2 घोड़ों सहित समाई बग्घी, घोड़े घायल

संवाददाता

लखनऊ। लालजी टंडन वार्ड के नरौना गांव में एक खुले निर्माणाधीन नाले में बग्घी गिरने से दो घोड़े गंभीर रूप से घायल हो गए। बग्घी चालक बाल–बाल बच गया। इस घटना ने नगर निगम की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जानकारी के अनुसार, नरौना गांव में जल निकासी के लिए करीब एक किलोमीटर लंबे नाले का निर्माण पिछले एक वर्ष से चल रहा है। यह कार्य न तो समय पर पूरा हुआ है और न ही सुरक्षा के कोई इंतजाम किए गए हैं। नाले के चारों ओर न तो बैरिकेडिंग लगाई गई है और न ही चेतावनी बोर्ड। इसी लापरवाही के कारण सड़क से गुजर रही बग्घी के घोड़े अचानक खुले नाले में फिसल गए, जिससे बग्घी पलट गई। हादसे के समय बग्घी पर सवार चालक किसी तरह कूदकर अपनी जान बचाने में सफल रहा। शोर सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों और बग्घी मालिक ने मिलकर कड़ी मशक्कत के बाद घोड़ों को नाले से बाहर निकाला। दोनों घोड़े घायल हो गए हैं, जिनका स्थानीय स्तर पर इलाज कराया जा रहा है।स्थानीय निवासी विजय पाल ने बताया कि यह नाला धर्म यादव के घर से काकोरी मोड़ के पास सर्वेश यादव के मकान तक बनाया जा रहा है। एक साल बीत जाने के बाद भी निर्माण कार्य अधूरा है। उन्होंने सबसे बड़ी लापरवाही नाले के आसपास घेराबंदी न होने को बताया, जिससे आए दिन हादसे की आशंका बनी रहती है। लोगों ने ठाकुरगंज की उस घटना का भी जिक्र किया, जहां बारिश के दौरान खुले नाले में गिरकर एक व्यक्ति की मौत हो गई थी।

यूपी की पहली इंटरनेशनल फिल्म सिटी में होगी 'मॉम–2' की शूटिंग

सेट के लिए शुरू हुई लैंड मैपिंग, 20 दिन में तैयार होगा शूटिंग सेट
फरवरी के अंत या मार्च की शुरुआत में शुरू होगी फिल्म की शूटिंग
सीएम योगी आदित्यनाथ का ड्रीम प्रोजेक्ट है इंटरनेशनल फिल्म सिटी
गौतमबुद्ध नगर के जेवर क्षेत्र में विकसित की जा रही इंटरनेशनल फिल्म सिटी
उत्तर प्रदेश को फिल्म, ओटीटी, वेब सीरीज समेत एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का राष्ट्रीय–अंतरराष्ट्रीय केंद्र बनाना है सीएम योगी का विजन

लखनऊ ब्यूरो

लखनऊ/ग्रेटर नोएडा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ड्रीम प्रोजेक्ट 'इंटरनेशनल फिल्म सिटी' ने अब जमीनी रफ्तार पकड़ ली है। गौतमबुद्ध नगर के जेवर क्षेत्र में विकसित की जा रही उत्तर प्रदेश की इस पहली इंटरनेशनल फिल्म सिटी में पहली फिल्म शूटिंग के रूप में 'मॉम–2' का फिल्मांकन होने जा रहा है। फिल्म सिटी परिसर में शूटिंग को लेकर प्रारंभिक तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। परियोजना का निर्माण कर रहे बोनी कपूर और भूटानी ग्रुप के ज्वाइंट वेंचर 'बेव्यू भूटानी फिल्म सिटी प्राइवेट लिमिटेड' ने जमीन की मैपिंग का कार्य शुरू कर दिया है। अधिकारियों के अनुसार, मैपिंग पूरी होने के बाद करीब 20 दिनों के भीतर शूटिंग सेट तैयार कर लिया जाएगा, जिसके बाद फिल्म की शूटिंग शुरू होने की संभावना है। उल्लेखनीय है कि इंटरनेशनल फिल्म सिटी प्रोजेक्ट का कार्य बॉलीवुड के प्रसिद्ध निर्माता–निर्देशक बोनी कपूर व भूटानी ग्रुप को संयुक्त रूप से मिला है। इस कंपनी ने यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा) के साथ एग्रीमेंट साइन किया है। यीडा द्वारा लेआउट प्लान को मंजूरी दिए जाने के बाद परियोजना के पहले चरण की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। बेव्यू भूटानी फिल्म सिटी प्रोजेक्ट के जीएम राजीव अरोड़ा ने बताया कि शूटिंग की तैयारियों के साथ–साथ फिल्म सिटी के निर्माण कार्य की प्रक्रिया भी शुरू की जा रही है। जमीन की मैपिंग पूरी होने के बाद करीब 20 दिनों के भीतर शूटिंग सेट तैयार कर लिया जाएगा, जिससे फिल्म निर्माण से जुड़ी गतिविधियां शुरू हो सकेंगी। इसके साथ ही फिल्म सिटी के निर्माण का कार्य भी शुरू हो जाएगा और जल्द ही सीएम योगी व पीएम मोदी के कर कमलों से इसका विधिवत शुभारंभ होने की संभावना है। उन्होंने बताया कि बोनी कपूर की कंपनी ने ही 2017 में रिलीज हुई बॉलीवुड फिल्म 'मॉम' को प्रोड्यूस किया था और अब उन्होंने इसके दूसरे पार्ट की शूटिंग को यूपी में करने का महत्वपूर्ण

निर्णय लिया है। इंटरनेशनल फिल्म सिटी यमुना एक्सप्रेसवे के सेक्टर–21 में विकसित की जा रही है। यह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, जिसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश को फिल्म, ओटीटी, वेब सीरीज़ समेत एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का राष्ट्रीय–अंतरराष्ट्रीय केंद्र बनाना है। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निकट विकसित हो रही यह फिल्म सिटी आधुनिक इन्फ्रास्ट्रक्चर, बेहतर कनेक्टिविटी और वर्ल्ड–क्लास सुविधाओं के साथ प्रदेश को एक एंटरटेनमेंट और एवियेशन हब के रूप में स्थापित करेगी। उद्योग विशेषज्ञों का मानना है कि फिल्म सिटी की औपचारिक शुरुआत से पहले 'मॉम–2' जैसी फिल्म की शूटिंग इस बात का संकेत है कि यूपी की फिल्म पॉलिसी और इन्फ्रास्ट्रक्चर को लेकर फिल्म इंडस्ट्री का भरोसा तेजी से बढ़ रहा है। यह परियोजना आने वाले समय में मुंबई समेत देश के अन्य फिल्म निर्माण केंद्रों का एक सशक्त विकल्प बन सकती है।

रेयर-अर्थ संकट के बाद 2026-27 में 18% तक उछाल संभव, ई-दोपहिया बिक्री में फिर आएगी रफ्तार?

दिल्ली ब्यूरो

नई दिल्ली। दुर्लभ खनिजों की आपूर्ति में सुधार से देश में इलेक्ट्रिक दोपहिया (ई–दोपहिया) वाहनों की बिक्री अगले वित्त वर्ष 2026–27 के दौरान 16–18 फीसदी बढ़ सकती है। हालांकि, चालू वित्त वर्ष 2025–26 में आपूर्ति शृंखला बाधाओं के कारण ई–दोपहिया वाहनों की बिक्री में वृद्धि 12–13 फीसदी तक सीमित रह सकती है। क्रिसिल रेटिंग्स ने एक रिपोर्ट में कहा, चालू वित्त वर्ष इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों की वृद्धि अस्थायी रूप से दुर्लभ खनिजों (रेयर–अर्थ मैग्नेट) की आपूर्ति में व्यवधान और आंतरिक दहन इंजन (आईसीई) मॉडलों पर जीएसटी युक्तिकरण के कारण धीमी रह सकती है। हालांकि, हाल के महीनों में ई–दोपहिया वाहनों की बिक्री में सुधार हुआ है। वित्त वर्ष 2024–25 में इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों की बिक्री में वृद्धि की रफ्तार 22 फीसदी रही थी। क्रिसिल रेटिंग्स के वरिष्ठ निदेशक अनुज सेठी ने कहा, दुर्लभ खनिजों की कमी से उत्पन्न आपूर्ति व्यवधान ने साल के मध्य में इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों की बिक्री को प्रभावित किया। खनिज की उपलब्धता में सुधार जैसे–जैसे इन खनिजों की उपलब्धता में सुधार हुआ और आईसीई मॉडल में जीएसटी कटौती के साथ मूल्य में संशोधन हुआ, मूल उपकरण विनिर्माता (ओईएम) कंपनियों ने ग्राहकों को

कीमतों में छूट दी। साथ ही, कम कीमत वाले इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों के मॉडल पेश किए, ताकि आईसीई–ईवी मूल्य अंतर को कम किया जा सके। 62% बाजार पर पुरानी कंपनियों का दबदबा क्रिसिल रेटिंग्स की निदेशक पूनम उपाध्याय ने कहा, पुरानी कंपनियों की बाजार हिस्सेदारी एक साल पहले के 47 फीसदी से बढ़कर जनवरी, 2026 तक 62 फीसदी पहुंच गई। यह नई कंपनियों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन है। बाजार हिस्सेदारी में यह बढ़ोतरी पुरानी कंपनियों के मजबूत डीलर नेटवर्क और आपूर्ति तंत्र के साथ एंट्री–लेवल और मिड–प्राइस इलेक्ट्रिक मॉडल की बढ़ी हुई रेंज को दिखाती है। विश्वसनीयता और सर्विस महत्वपूर्ण कारण बने हुए हैं, जहां पुरानी ओईएम कंपनियां अभी अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं। चलाने की कम लागत से बढ़ रहा ओनरशिप रिपोर्ट में कहा गया है कि जीएसटी दरों में कटौती से आईसीई गाड़ियों की खरीदने की लागत तो घटी है, लेकिन चलाने की लागत के मामले में ई–दोपहिया वाहन बेहतर हैं। इनकी चलाने की लागत करीब 3 पैसे/किमी है, जबकि आईसीई गाड़ियों के लिए यह 2–2.5 रुपये/किमी है। इससे कुल ओनरशिप लागत में ई–दोपहिया वाहनों का फायदा बना हुआ है, भले ही सब्सिडी कम हो रही हो।

एनटीपीसी सिंगरौली संभागीय नाट्य समारोह में 'दिल की दुकान' ने जीता दर्शकों का दिल

"मंच पर उतरी मानवीय संवेदनाएँ, 'दिल की दुकान' ने छोड़ी गहरी छाप"

बीएनई

सिंगरौली। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी, लखनऊ के सौजन्य से आयोजित संभागीय नाट्य समारोह के अंतर्गत एनटीपीसी सिंगरौली के कर्मचारी विकास केंद्र में प्रसिद्ध नाट्य कृति 'दिल की दुकान' का सफल एवं प्रभावशाली मंचन किया गया। इस नाटक के लेखक राजेंद्र शर्मा हैं तथा निर्देशन रतन राठौर के कुशल मार्गदर्शन में संपन्न हुआ। अनुभूति नाट्य इकाई, कानपुर द्वारा प्रस्तुत यह हास्य नाट्य प्रस्तुति मानवीय संवेदनाओं, रिश्तों की जटिलताओं और सामाजिक यथार्थ को अत्यंत प्रभावी ढंग से दर्शाने में सफल रही। इस अवसर पर प्रज्ञा नायक, अध्यक्षा, वनिता समाज, सी. एच. किशोर कुमार, महाप्रबंधक (प्रचालन एवं अनुरक्षण), विभिन्न विभाग प्रमुख, श्री प्रशांत, कार्यक्रम प्रभारी, संगीत नाटक अकादमी, दिनेश श्रीवास्तव, कार्यक्रम ऑब्जर्वर, संगीत नाटक अकादमी, वनिता समाज की वरिष्ठ सदस्याएं, यूनियन एवं एसोसिएशन के प्रतिनिधिगण, ग्राम प्रधान, प्राचार्यगण, पत्रकार बंधु एवं बड़ी संख्या में दर्शक उपस्थित रहे। नाटक की कथावस्तु ने आधुनिक जीवन में मानवीय भावनाओं के बदलते स्वरूप को गहराई से प्रस्तुत किया। कलाकारों

ने अपने सजीव अभिनय, भावपूर्ण संवाद एवं सशक्त मंच–सज्जा के माध्यम से प्रत्येक पात्र को जीवंत बना दिया। प्रस्तुति के दौरान सभागार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा और दर्शकों ने कलाकारों का उत्साहवर्धन किया। मुख्य अतिथि संदीप नायक, परियोजना प्रमुख एवं कार्यकारी निदेशक, एनटीपीसी सिंगरौली ने अपने संबोधन में कहा कि 'दिल की दुकान' जैसी प्रस्तुतियाँ समाज को आत्मचिंतन की दिशा में प्रेरित करती हैं। उन्होंने कहा कि कला केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं, बल्कि मानवीय मूल्यों, संवेदनाओं और सामाजिक जागरूकता का सशक्त माध्यम भी है। उन्होंने अनुभूति नाट्य इकाई, कानपुर तथा सभी कलाकारों की सराहना करते हुए उन्हें शुभकामनाएँ प्रदान दी। कार्यक्रम के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले कलाकारों को सम्मानित भी किया गया। आयोजन का सफल संचालन एवं व्यवस्थापन डॉ ओम प्रकाश, उप महाप्रबंधक(मानव संसाधन) द्वारा किया गयाद्य यह नाट्य प्रस्तुति संभागीय नाट्य समारोह की गरिमा को और अधिक सुदृढ़ करने के साथ–साथ दर्शकों के लिए एक यादगार सांस्कृतिक अनुभव सिद्ध हुई।

भदोही बना सनातन संस्कृति की मिसाल, कालीन पर उकेरी रामेश्वरम सेतु की छवि

प्रधानमंत्री मोदी से निर्मित कालीन का लोकार्पण कराने की मंशा
पीएमओ से मांगा गया समय, स्वीकृति मिलते ही दिल्ली जाएंगे निर्यातक

बीएनई

भदोही। कालीन नगरी भदोही की एक प्रतिष्ठित निर्यात फर्म ने कालीन पर रामेश्वरम में बने श्रीराम सेतु को उकेर कर सनातन संस्कृति को समाज से जोड़ने का प्रयास किया है। कालीन नगरी के कुशल बुनकरों की थिरकती उंगलियों से बने इस आकर्षक कालीन का लोकार्पण देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से करने का संकल्प लेकर निर्यातक वैभव बरनवाल एवं अजय राय ने कहा कि आज की युवा पीढ़ी मुगल कालीन उद्भव व पाश्चात्य संस्कृति को अपना

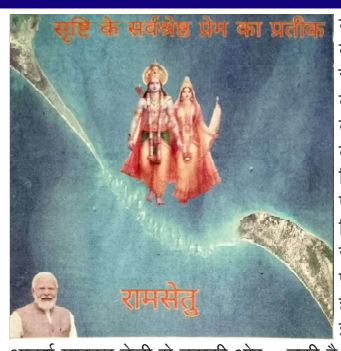

आदर्श मानकर तेजी से उसकी ओर आकर्षित हो रही है। जिससे समाज का नैतिक पतन हो रहा है। बच्चों व युवा पीढ़ी को राम–कृष्ण के देश में ऐसे कालीन का विमोचन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से करने के लिए फर्म के निर्यातक कृत संकल्पित है एक अनौपचारिक वार्ता में निर्यातको ने बताया कि आज जबकि हमारी पीढ़ी मुगल और पश्चिम सभ्यता के वशीभूत होकर अपने गौरवशाली इतिहास को विस्मित कर चुकी है ऐसे में मर्यादा पुरुषोत्तम राम के दिखाएं गए मार्ग पर चलकर और भगवान श्रीकृष्ण के गीता में बताए गए उपदेशों का पालन करके ही पुनःभारत को सोने की चिड़िया और विश्व गुरु के रूप में स्थापित किया जा सकता है। निर्यातकों ने कहा कि 2014 में जब मोदी जी पहली बार देश के प्रधानमंत्री बने तभी से हम सब उनके विचारों से प्रभावित हैं और उन्हीं के बताए हुए विचारों से प्रभावित होकर कालीन उद्योग में खोज करने लगे हमने कालीन को न सिर्फ सनातन से जोड़ने का कार्य किया है बल्कि देश के सांस्कृतिक धरोहरों को भी कालीन पर उतारने में संकोच नहीं किया है। ब्रह्मांड के सर्वोत्तम प्रेम का प्रतीक रामेश्वरम सेतु हमने इसी विचारधारा के तहत कालीन पर उतारा है। हम अपने देश के प्रधानमंत्री को समर्पित करेंगे और उनसे यह मांग करेंगे कि रामेश्वरम सेतु को प्रेम का प्रतीक मानते हुए ऐतिहासिक धरोहर के रूप में इसको संरक्षित करें। निर्यातकों ने बताया कि उसी कड़ी में नवग्रह सुखासन का निर्माण और आने वाले समय में कालीन को सनातन से जोड़ने के अनेक उपाय किए जाएंगे। उन्होंने केंद्र सरकार से सहयोग की अपेक्षा है निर्यात को ने बताया कि प्रधानमंत्री से मिलने के लिए समय मांगा गया है।

एसजेवीएन ने असम में 70 मेगावाट धुबरी सौर ऊर्जा परियोजना का सीओडी हासिल किया

बीएनई

शिमला। भूपेंद्र गुप्ता, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एसजेवीएन ने अवगत कराया है कि एसजेवीएन ने असम में 70 मेगावाट धुबरी सौर ऊर्जा परियोजना की वाणिज्यिक प्रचालन तिथि (सीओडी) को सफलतापूर्वक हासिल कर लिया है। कंपनी ने नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करते हुए इस परियोजना को पूर्ण स्वामित्व वाली अधीनस्थ कंपनी, एसजेवीएन ग्रीन एनर्जी लिमिटेड (एसजीईएल) के माध्यम से पूर्ण किया है, जो कंपनी की रिन्यूएबल एनर्जी यात्रा में एक और बड़ा मील का पत्थर है। 70 मेगावाट धुबरी सौर ऊर्जा परियोजना को असम के धुबरी जिले के गांव खुदीगांव पीटी. II में 330 एकड़ की लीज़ आधारित भूमि पर 367.44 करोड़ रूपए की परियोजना लागत पर विकसित किया गया है। इस परियोजना के प्रचालन से प्रथम वर्ष में 141.13 मिलियन यूनिट विद्युत उत्पादन और 25 वर्षों की अवधि में कुल संचयी विद्युत उत्पादन लगभग 3,230 मिलियन यूनिट होने की संभावना है। किफायती और स्वच्छ विद्युत की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए परियोजना से उत्पादित विद्युत का अधिकतम उपयोग शुल्क 3.92 रूपए प्रति यूनिट तय किया गया है। उत्पादित विद्युत की आपूर्ति असम पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (एपीडीसीएल) को की जाएगी। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिनांक 4 मार्च, 2024 को आदिलाबाद, तेलंगाना से इस परियोजना की नींव रखी थी। यह परियोजना असम राज्य में प्रथम बड़े पैमाने की सौर परियोजना है और साथ ही एसजेवीएन की उत्तर पूर्व क्षेत्र में प्रथम प्रचालनरत परियोजना भी है। भारत सरकार के वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के लक्ष्य को हासिल करने में धुबरी सौर ऊर्जा परियोजना का कमीशनिंग एक महत्वपूर्ण योगदान है। स्वच्छ ऊर्जा पोर्टफोलियो को सुदृढ़ करने के अतिरिक्त, इस परियोजना से कार्बन उत्सर्जन में लगभग 1,58,270 टन की कमी आने की संभावना है, जिससे जलवायु परिवर्तन के लिए भारत की प्रतिबद्धता और सुदृढ़ होगी। इस परियोजना ने अनेक प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोज़गार के अवसर भी सृजित किए हैं, जिससे ग्रीन जॉब्स निर्मित करने में सहयोग मिला है और स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिला है।

संक्षिप्त

आईसीसी चेयरमैन जय शाह से मिले फीफा अध्यक्ष गियानी इनफैनटिनो,तस्वीर साझा कर जताई खुशी

एजेंसी

नई दिल्ली। वैश्विक खेल जगत से जुड़ी एक अहम तस्वीर इन दिनों सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई है। फीफा अध्यक्ष गियानी इनफैनटिनो ने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) के चेयरमैन जय शाह से मुलाकात की और इसकी तस्वीर साझा करते हुए अपनी खुशी जाहिर की। क्रिकेट और फुटबॉल, दुनिया के दो सबसे लोकप्रिय खेलों के शीर्ष प्रशासकों की यह मुलाकात कई मायनों में खास मानी जा रही है। इनफैनटिनो ने सोशल मीडिया पर जताई खुशी फीफा अध्यक्ष गियानी इनफैनटिनो ने बुधवार देर रात इंस्टाग्राम पर तस्वीर साझा करते हुए जय शाह की जमकर तारीफ की। उन्होंने अपने कैप्शन में लिखा, आईसीसी चेयरमैन जय शाह से मिलना मेरे लिए बहुत खुशी की बात थी। क्रिकेट जैसे खूबसूरत खेल को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने जो शानदार काम किया है, वह काबिले–तारीफ है। मैं उन्हें और पूरी क्रिकेट बिरादरी को शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि क्रिकेट को ओलंपिक खेलों में दोबारा शामिल किया जा रहा है। मैं भविष्य में साथ काम करने और सहयोग को लेकर उत्साहित हूं, ताकि खेलों के जरिए दुनिया को एकजुट किया जा सके। क्रिकेट और फुटबॉल का साझा मंच यह मुलाकात ऐसे समय पर हुई है, जब खेलों के वैश्विक स्तर पर सहयोग और विस्तार की चर्चा जोरों पर है। क्रिकेट को ओलंपिक में दोबारा शामिल किए जाने की प्रक्रिया और फुटबॉल की पहले से मजबूत वैश्विक मौजूदगी, दोनों खेलों को और व्यापक मंच देने की दिशा में यह बातचीत अहम मानी जा रही है। एक ही साल में टी20 और फीफा वर्ल्ड कप खास बात यह है कि इसी साल खेल प्रेमियों को दो बड़े महाकुंभ देखने को मिलेंगे। एक ओर आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप का आयोजन होगा, वहीं दूसरी ओर फीफा वर्ल्ड कप भी खेल जगत का सबसे बड़ा आकर्षण रहेगा।

पहली बार "संत कबीर उत्सव" का आयोजन 6 फरवरी को

बृजेश चतुर्वेदी

कन्नौज। संत कबीर अकादमी (संस्कृति विभाग, उत्तर प्रदेश) एवं जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वावधान में कन्नौज में पहली बार "संत कबीर उत्सव" का आयोजन किया जा रहा है। यह सांस्कृतिक आयोजन 06 फरवरी को सायं 03:00 बजे मुक्ताकाशी मंच, रोमा स्मारक, जी.टी. रोड में आयोजित होगा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में समाज कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) एवं विधायक कन्नौज असीम अरुण उपस्थित रहेंगे। उत्सव में विभिन्न प्रतिष्ठित कलाकार अपनी प्रस्तुतियों से कार्यक्रम को समृद्ध करेंगे। इनमें वीना राणा (लखनऊ) द्वारा कबीर पर आधारित नृत्य नाटिका प्रेरणा राणा (लखनऊ) द्वारा नृत्य नाटिका नीतू रावत (मथुरा) द्वारा चरकुला, होली एवं मयूर नृत्य संग्राम सिंह (कन्नौज) द्वारा आल्हा गायन राधेश्याम पाल "बंदा बैरागी" कबीर बैंड की प्रस्तुति प्रमुख आकर्षण होंगी। यह उत्सव संत कबीर की विचारधारा, भक्ति परंपरा और लोक–सांस्कृतिक विरासत को जन–जन तक पहुंचाने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है। आयोजकों ने जनपदवासियों से अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर कार्यक्रम को सफल बनाने की अपील की है।

खरौली पेयजल योजना पर 'जल अर्पण' कार्यक्रम सम्पन्न

ग्रामीणों को मिली नियमित स्वच्छ जलापूर्ति की सौगात

बृजेश चतुर्वेदी

कन्नौज। जल जीवन मिशन के अन्तर्गत जनपद के विकास खण्ड सौरिख की खरौली पेयजल योजना का निर्माण मैसर्स जी०वी०पी०आर० इंजीनियर्स द्वारा सफलतापूर्वक पूर्ण किया गया है। योजना के अन्तर्गत नलकूप, 175 कि.ली. क्षमता का अवर जलाशय, विस्तृत पाइप लाइन नेटवर्क एवं क्रियाशील नल जल संयोजनों सहित सभी कार्य पूर्ण कर लिए गए हैं, जिसके फलस्वरूप ग्राम खरौली में नियमित एवं सुरक्षित जलापूर्ति सुनिश्चित हो गई है। इस अवसर पर विधायक अर्चना पाण्डेय, विधानसभा क्षेत्र छिबरामऊ की गरिमामयी उपस्थिति में खरौली पेयजल योजना स्थल पर "जल अर्पण" कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि द्वारा ग्रामीणों को जल संकल्प दिलाया गया तथा योजना को विधिवत ग्राम प्रधान को हस्तगत किया गया। उन्होंने कहा कि खरौली पेयजल

योजना के सफल क्रियान्वयन से ग्रामवासियों को शुद्ध पेयजल की स्थायी सुविधा प्राप्त हुई है, जो जल जीवन मिशन के "हर घर जल" संकल्प को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इस अवसर पर वी०डब्लू०एस०सी० के सदस्यों को उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया। वहीं एफ०टी०के० किट से जल परीक्षण हेतु प्रशिक्षित महिलाओं द्वारा जल गुणवत्ता जांच की प्रक्रिया का प्रदर्शन किया गया, जिससे ग्रामीणों को स्वच्छ जल के महत्व और परीक्षण की जानकारी प्राप्त हुई। कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यालय के छात्र–छात्राओं द्वारा प्रभात फेरी निकालकर जल संरक्षण एवं स्वच्छ जल के प्रति जागरूकता का संदेश दिया गया। कार्यक्रम में मनोज कुमार पोरवाल, खण्ड विकास अधिकारी सौरिख, ब्लाक प्रमुख प्रतिनिधि सचिन बाथम, सुरेन्द्र कुमार, अधिशासी अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण), पवन कुमार राजपूत, ग्राम प्रधान खरौली, जीशान आलम, डी०सी० डीपीएगयू, चारु उपाध्याय, डीपीएम टीपीआई तथा निर्माण फर्म के परियोजना प्रबन्धक रौनक सुतारिया सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति, अधिकारी एवं ग्रामवासी उपस्थित रहे।

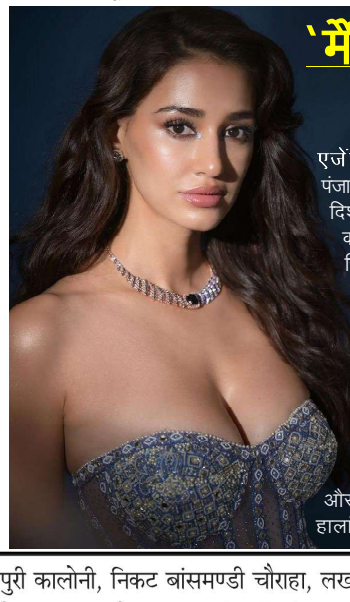

'मैं अभी प्यार में पड़ रहा हूं', दिशा पाटनी को डेट करने की खबरों पर सिंगर तलविंदर ने पहली बार दी प्रतिक्रिया

एजेंसी

पंजाबी सिंगर तलविंदर इन दिनों अपने गानों से ज्यादा अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चाओं में हैं। तलविंदर का नाम इन दिनों बॉलीवुड अभिनेत्री दिशा पाटनी के साथ जोड़ा जा रहा है। दोनों को कई मौकों पर साथ देखा गया, जिसके बाद ऐसा कहा जा रहा है कि दिशा पाटनी तलविंदर को डेट कर रही हैं। अब डेटिंग की खबरों पर तलविंदर ने पहली बार प्रतिक्रिया दी है। जानिए तलविंदर ने दिशा को डेट करने पर क्या कुछ कहा? द हॉलीवुड रिपोर्टर इंडिया के साथ बातचीत में तलविंदर ने डेटिंग की खबरों पर प्रतिक्रिया देते हुए बताया कि उनकी दिशा पाटनी से मुलाकात कब हुई थी। सिंगर ने बताया कि उनकी और दिशा की मुलाकात हाल ही में हुई है। उनकी जान–पहचान नूपुर सेनन और स्टेबिन बेन की शादी से ठीक पहले शुरू हुई थी। ये एक सामान्य दोस्ती के रूप में शुरू हुई थी। डेटिंग की खबरों पर सिंगर ने कहा कि हम अभी भी एक–दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे हैं। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा क्योंकि अगर लोग अफवाहें फैलाने की कोशिश करेंगे, तो मैं उन्हें अफवाहें ही रहने दूंगा। प्यार को लेकर तलविंदर ने कही ये बात दिशा पाटनी से प्यार और फीलिंग्स को लेकर तलविंदर ने कहा कि मैं हर दिन प्यार में पड़ जाता हूं। मैं अभी प्यार में पड़ रहा हूं। हालांकि, इस दौरान तलविंदर ने दिशा का नाम स्पष्ट रूप से नहीं लिया, लेकिन इस बयान के समय ने दोनों के बीच रोमांटिक संबंध की अटकलों को और भी तेज कर दिया है। तलविंदर के इस बयान से दिशा और उनके रिलेशन की खबरों को और भी बल मिलता है। हालांकि, अभी तक दिशा पाटनी ने भी तलविंदर के साथ अपने रिश्ते पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। नूपुर की शादी के दौरान साथ दिखे थे दिशा और तलविंदर हाल ही में नूपुर सेनन की शादी और मुंबई में हुए रिशेप्सन के दौरान दिशा और तलविंदर एक साथ देखे गए थे। इस दौरान दोनों के बीच की नजदीकियों को देखते हुए लोगों ने उनके अफेयर की चर्चाएं शुरू कर दीं। हालांकि, इस दौरान तलविंदर अपना चेहरा छिपाते नजर आए थे। वहीं नूपुर के रिसेप्शन में भी तलविंदर और दिशा साथ में दिखे थे।

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक **धर्मेन्द्र सिंह** द्वारा शौर्य प्रिंटर्स, शिवपुरी कालोनी, निकट बांसमण्डी चौराहा, लखनऊ से मुद्रित तथा एमआईजी-47, सेक्टर-ई, अलीगंज, लखनऊ (उ.प्र.) से प्रकाशित
सम्पादक-अंजू सिंह (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र लखनऊ होगा) Email-lkojunction@gmail.com. RNI NO.-UPHIN/2015/64743